सम्पादकीय

आतंकी पन्नू का हमदर्द अमेरिका

अमेरिका दुनिया का शक्तिशाली देश है। उसके इशारे पर पलभर में समीकरण बनते और बिगड़ते हैं। एक खास बात यह है कि अमेरिकी खुद को सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। हालांकि अति आत्मविश्वास या घमंड के चलते उन्हें बहुत नुक्सान भी उठाना पड़ रहा है। विडम्बना यह है कि आतंकवाद चरमपंथ और हिंसा पर एक्शन अमेरिका अपनी सहूलियत के हिसाब से लेता है। क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी सुविधा के हिसाब से नहीं हो सकता। इस मामले में भारत ने हमेशा ही अमेरिका सहित कई देशों को आइना दिखाया। आतंकवाद पर अमेरिका ने हमेशा दोहरा रवैया अपनाया। खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस के सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश में न्यूयार्क के दक्षिणी जिले की अमेरिकी जिला कोर्ट ने भारत के राष्ट्रीय सलाहकार अजित डोभाल, पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल को सम्मन भेजा है। इस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। अमेरिकी कोर्ट ने आरोपी दो व्यक्तियों निखिल गुप्ता और विक्रम यादव को भी सम्मन भेजा है। पन्नू हत्या की साजिश के मामले में अमेरिका पहले भी भारत पर कई अनर्गल आरोप लगा चुका है।

क्या अमेरिका आतंकवादी पन्नू का इतिहास नहीं जानता? क्या अमेरिका नहीं जानता कि सिख फॉर जस्टिस संगठन एक गैर कानूनी संगठन है, जिस पर भारत ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। पन्नू भारत की सम्प्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के मकसद से राष्ट्र विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रहता है और भारत के विरुद्ध जहर उगलता रहता है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तो खालिस्तानियों का समर्थन करने के पीछे सत्ता की मजबूरियां साफ दिखाई देती हैं लेकिन अमेरिका का आतंकवादी पन्नू का हमदर्द हो जाना हैरानी भरा है। अमेरिका भारत को अपना रणनीतिक सहयोगी मानता है लेकिन इसके बावजूद वह भारत पर दबाव बनाने के लिए ऐसी हरकतें करता रहता है। हो सकता है कि अमेरिका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यात्रा से पहले भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए कोई चाल चल रहा हो। भारत पहले ही पन्नू की हत्या की साजिश के आरोपों का खंडन कर चुका है, पर सवाल यह उठता है कि जो शख्स भारत के खिलाफ लगातार आग उगल रहा हो, भारत में हुई कई आतंकी कार्रवाई में शामिल रहा हो, भारत के विमान को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा हो, भारत में हो रहे क्रिकेट विश्व कप के दौरान बम धमाके की बात कर रहा हो, क्या भारत सरकार को उसकी आरती उतारनी चाहिए? अमेरिका क्यों नहीं समझ रहा है कि हो सकता है कि गुरपतवंत पन्नू भी पाकिस्तानी अमेरिकी डेविड कोलमैन हेडली की तरह अमेरिका में बैठकर खतरनाक आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा हो? क्या जिस तरह अमेरिका डेविड कोलमैन हेडली के मुंबई हमलों को अंजाम देने के बाद हरकत में आया था वैसा ही गुरपतवंत सिंह पन्नू के साथ भी करेगा? क्या केवल अमेरिका को ही अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए किसी भी देश में एक्शन लेने का अधिकार है? भारत यह कभी भूल नहीं सकता कि जब भारतीय अधिकारी हेडली से पूछताछ करने अमेरिका गए थे तब उन्हें हेडली से मिलने भी नहीं दिया गया था। क्या अमेरिका और कनाडा किसी आतंकवादी को अपने घर में आरती उतारते रहे हैं, इसकी कोई नजीर है?

क्वाड की बैठक ने उड़ाई जिनपिंग की नींद!

चार सदस्यीय क्वाड, जो एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत को बनाए रखने की वकालत करती है। चीन का दावा है कि इस समूह का मकसद उसके उदय को रोकना है।कुछ समय पूर्व चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जहां तक क्वाड का संबंध है, मुझे लगता है कि भारत इस तंत्र की मंशा को हमसे बेहतर जानता है। क्या इसका इरादा चीन के खिलाफ एक छोटे-से गुट को खड़ा करना नहीं है? कुछ ही दिन पहले ढाका में चीन के राजदूत ली जिमिंग ने बांग्लादेश को अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड गठबंधन में शामिल होने के खिलाफ आगाह करते हुए कहा था कि बीजिंग विरोधी क्लब में ढाका की भागीदारी के वजह से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को काफी नुकसान होगा।

अशोक भाटिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अमेरिका में चल रहे क्वाड शिखर सम्मेलन की शुरुआत में ही चीन पर निशाना साधा था । प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्वाड एक्टिव रहने के लिए बना है और यह किसी के खिलाफ नहीं है। बिना नाम लिए चीन पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि क्वाड के नेता नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था और संप्रभुता के सम्मान में खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि दुनिया में संघर्ष चल रहा है और क्वाड हर संघर्ष का शांतिपूर्ण सम्माधान चाहता है।उन्होंने कहा, 'क्वाड का साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर मिलकर काम करना पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम सभी नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'स्वतंत्र, खुला, समावेशी और समृद्ध हिंद-प्रशांत हमारी साझा प्राथमिकता और साझा प्रतिबद्धता है। हमने मिलकर स्वास्थ्य, सुरक्षा, उभरती टेक्नोलॉजी और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी पहल की है।' शायद इसी कारण अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को क्वाड देशों के नेताओं के साथ बात आपसी बातचीत में चीन की आलोचना करते हुए रिकॉर्ड किया गया है। बाइडेन को क्वाड देशों के नेताओं से यह कहते हुए रिकॉर्ड किया गया है, कि चीन उनकी परीक्षा ले रहा है।बाइडेन की ये बात, उभरते चीनी खतरे के प्रति अमेरिकी गंभीरता को दर्शाता है। बाइडेन की यह टिप्पणी शनिवार को क्वाड लीडर्स समिट के दौरान आई है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने भी हिस्सा लिया है।

शिखर सम्मेलन स्थल से पूल रिपोर्टर के बाहर निकलते समय उनकी शुरुआती टिप्पणी हॉट माइक पर कैद हो गई। बाइडेन को यह कहते हुए सुना गया, कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 'मेरे विचार से, चीन के हितों को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अपने लिए कुछ कूटनीतिक स्पेस खरीदना चाहते हैं।चीन, आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल मुद्दों सहित कई मोर्चों पर पूरे क्षेत्र में हम सभी का टेस्ट करते हुए आक्रामक व्यवहार करना जारी रखे हुआ है। साथ ही, उनका मानना है कि तीव्र प्रतिस्पर्धा के लिए गहन कूटनीति की आवश्यकता होती है। वहीं, बाद में एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने इस बाइडेन की इस फुसफुसाहट को संभालने की कोशिश की और कहा, कि मुझे नहीं लगता, कि इस पर विस्तार से बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। यह पहले जो कहा गया है, उसके मुताबिक ही है, और मुझे नहीं लगता कि यह बहुत आश्चर्य की बात होगी, कि हमारी अंदरूनी आवाज हमारी बाहरी आवाज से मेल खाती है। मुझे लगता है कि यह आश्चर्य की बात नहीं है, कि चीन एजेंडे में रहा होगा। यह एक इंडो-पैसिफिक सम्मेलन है। यह एक इंडो-पैसिफिक साझेदारी है। चीन इंडो-पैसिफिक में एक प्रमुख देश है। लेकिन मुझे लगता है कि यह कहना भी उचित है कि एजेंडे में कई अन्य विषय भी थे।आपको बता दें, कि चीन दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर दोनों में उग्र क्षेत्रीय विवादों में उलझा हुआ है।चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है। वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई और ताइवान ने भी इस पर जवाबी दावे किए हैं। आपको बता दे कि आखिर क्या है क्वाड जिसके कारण जिनपिंग की नींद उडी हुई है । क्वाड शब्द 'क्वाड्रीलेटरल सुरक्षा वार्ता' के क्वाड्रीलेटरल (चतुर्भुज) से लिया गया है। इस समूह में भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। क्वाड जैसे समूह को बनाने की बात पहली बार 2004 की सुनामी के बाद हुई थी जब भारत ने अपने और अन्य प्रभावित पड़ोसी देशों के लिए बचाव और राहत के प्रयास किए और इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी शामिल हो गए थे।लेकिन इस आइडिया का श्रेय जापान के पूर्व प्रधान मंत्री शिंज़ो आबे को दिया जाता है। 2006 और 2007 के बीच आबे क्वाड की नींव रखने में कामयाब हुए और चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता की पहली अनौपचारिक बैठक वरिष्ठ अधिकारीयों के स्तर पर अगस्त 2007 में मनीला में आयोजित की गई। उसी साल क्वाड के चार देशों और सिंगापुर ने मालाबार के नाम से बंगाल की खाड़ी में एक नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लिया था। इस सब पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए क्वाड देशों से यह बताने को कहा था कि क्या क्वाड एक बीजिंग विरोधी गठबंधन है? क्वाड को एक झटका और लगा जब कुछ समय बाद ही ऑस्ट्रेलिया इससे अलग हो गया। दस साल बाद 2017 में मनीला में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान भारत-ऑस्ट्रेलिया-जापान-अमेरिका संवाद के साथ क्वाड वापस अस्तित्व में आया।यह बैठक इन देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के मनीला पहुँचने से कुछ घंटे पहले हुई। यह वार्ता इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी कि उस समय भारत और चीन के बीच डोकलाम में गतिरोध चल रहा था।2017 में गति मिलने के बाद क्वाड के विदेश मंत्री अक्टूबर 2020 में टोक्यो में मिले और कुछ ही महीनों बाद इस साल मार्च में जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के कुछ ही हफ़्तों बाद अमेरिका ने क्वाड के वर्चुअल शिखर सम्मलेन की मेज़बानी की। चीन शुरू से ही क्वाड को चार विरोधी देशों का समूह मानता रहा है। उसे लगता है कि क्वाड के ये चार देश उसकी बढ़ती ताकत के खिलाफ गुटबंदी कर रहे हैं।क्वाड के देशों ने सैन्य क्षेत्र को लेकर कोई सार्वजानिक बयान नहीं दिए हैं पर ये माना जाता है कि दक्षिण चीन सागर और हिन्द महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाना इन देशों की एक बड़ी प्राथमिकता है।रक्षा विशेषज्ञ सी उदय भास्कर भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त कमोडोर हैं। वे आजकल दिल्ली स्थित सोसाइटी फॉर पालिसी स्टडीज़ के निदेशक हैं। उनके अनुसार चीन क्वाड के ग्रुप को लेकर काफी चिंतित है। वे कहते है कि पिछले साल चीन इसे नीचा दिखाने की कोशिश कर चुका है। उनके एक मंत्री ने कहा था कि क्वाड समुद्र के पानी पर झाग जैसा है जो हवा से उड़ जायेगा। क्वाड चीन के लिए हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में बहुत बड़ी चुनौती हो सकता है, इसीलिए क्वाड की क्षमता देखते हुए चीन बहुत चिंतित है। उनका यह भी कहना था कि समुद्री क्षेत्र में चीन अपना दबदबा दक्षिण चीन सागर में और पूर्व सागर मे दिखाता रहा है। उनके अनुसार इस दबदबे की वजह से जहाँ दक्षिण चीन सागर में आसियान के देश प्रभावित हुए हैं, वहीं पूर्व सागर में जापान।वे कहतें हैं, दोनों क्षेत्रों में चीन एक चुपके-चुपके अपना दावा बढ़ाता दिख रहा है। दक्षिण चीन सागर में नाइन डैश लाइन और कृत्रिम इंस्टालेशन बना दिए हैं और तरह-तरह के क्षेत्रीय दावे कर दिए हैं। यह सब देखते हुए जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने कहा है कि समुद्री क्षेत्र में एक नियम आधारित व्यवस्था होनी चाहिए। पिछले साल नवंबर में भारतीय नौसेना ने बहुपक्षीय युद्धाभ्यास मालाबार का आयोजन हिंद महासागर में किया। इस अभ्यास में अमेरिकी नौसेना, जापानी मैरीटाइम सेल्फ़ डिफेंस फ़ोर्स और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने हिस्सा लिया। क्वाड देशों के इस युद्धाभ्यास को चीन के लिए एक संदेश की तरह देखा गया। कमोडोर भास्कर के अनुसार समुद्री क्षेत्र के अलावा चीन के साथ साइबर और स्पेस के क्षेत्रों में भी नियम आधारित व्यवस्था बनाने की कोशिश होनी चाहिए। वे कहते हैं, चीन को नियम आधारित व्यवस्था में लाने के लिए लोकतान्त्रिक देश अपना एक गुट बनाते हुए सिद्धांतों के लिए आगे बढ़ सकते हैं। उनका यह भी मानना था कि अगर यह चार देश मिलकर सहमति बना रहे हैं तो यह चीन के खिलाफ़ नहीं है बल्कि एक नियम आधारित व्यवस्था बनाने के लिए है। वे कहते हैं, क्वाड ग़ैर-सैनिक मुद्दों को आगे बढ़ा रहा है जिसमें कोविड महामारी के दौरान एक दूसरे से सहयोग करना और ज़रूरतमंद देशों की मदद करने की बात की गई है। गौरतलब है कि जब भारत पूरे विश्व की तरह कोरोना महामारी की पहली लहर से जूझ रहा था, उसी दौरान चीन की ओर से लद्दाख क्षेत्र के कई सीमा क्षेत्रों में घुसपैठ करने की खबरें आनी शुरु हुईं।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र हैं, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, आपको किन बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे काम में और जटिल मुद्दों को सुलझाने तथा सकारात्मक ऊर्जा को मजबूत करेंगे, बल्कि पारस्परिक संबंधों में भी, जहां यह सकारात्मकता हमें संवाद और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष
परिजनों के साथ सम्बंध मधुर होंगे। हेल्थ आज अच्छी रहेगी। हालांकि बाहर खाने-पीने से बचें। दोपहर के बाद अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। अस्वस्थ व्यक्तियों को स्वास्थ्य लाभ होगा। आर्थिक लाभ की पूरी संभावना है।

वृष
कार्यालय या व्यवसाय में काम अधूरा रहने से मन निराश रहेगा। यात्रा में विघ्न आ सकता है। आध्यात्मिकता और ईश्वर भक्ति से मन प्रसन्न रहेगा। हालांकि आप के काम योजनानुसार पूरे होंगे। अधूरे काम पूरे होंगे। धन लाभ की संभावना है।

मिथुन
परिजनों के साथ कोई विवाद हो सकता है। आपका आज का दिन मध्यम फलदायी रहेगा। दिन की शुरुआत में स्फूर्ति और आनंद का अनुभव होगा। आपकी रचनात्मकता से आप कठिन काम भी आसानी से बना पाएंगे।

कर्क
विदेश जाने के इच्छुक लोग आज सकारात्मक प्रयास कर सकते हैं। दोपहर के बाद नया काम या टारगेट मिल सकता है। कोई अधूरा काम आज पूरा हो सकेगा। व्यापार में बढ़ोतरी की संभावना हैं। गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी। काम का उत्साह बना रहेगा।

सिंह
किसी मीटिंग के लिए छोटी यात्रा हो सकती है। नए काम शुरू करने के लिए आज का दिन अनुकूल है। आज आप कुछ धार्मिक बने रहेंगे। कार्यालय या व्यावसायिक स्थल पर काम का भार अधिक रहेगा।

कन्या
आज नए काम का आरंभ करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। अधिक कार्य से आलस्य और मानसिक चिंता का अनुभव करेंगे। यात्रा आज लाभदायी नहीं है, परंतु दोपहर के बाद आपको कुछ नया करने की प्रेरणा मिलेगी। धार्मिक काम होंगे। किसी प्रिय पात्र से मुलाकात होगी।

तुला
आपको काम पूरा होने का उत्साह बना रहेगा। परिवार का वातावरण भी परिवर्तित होगा। आर्थिक लाभ की भी संभावना है। आज का दिन पारिवारिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में लाभ का अवसर लाया है।

वृश्चिक
आपका आज का दिन मिश्रित फलदायी है। आज आप चिंता से घिरे रहेंगे और शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा। परिवार में भी किसी से मतभेद रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद आप सभी कामों में अनुकूलता का अनुभव करेंगे।

धनु
स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज का दिन आनंदपूर्वक गुजरेगा। व्यापार करने वालों के लिए आज का दिन लाभदायी है। परिजनों तथा मित्रों के साथ अच्छे पलों को गुजारेंगे। किसी तरह का आर्थिक लाभ आपको हो सकता है।

मकर
दिन की शुरुआत में आप थोड़े कन्फ्यूज रहेंगे। दूसरों के साथ सामंजस्य बनाए रखें। वाणी मधुर बनाए रखें, इससे कोई भी काम आसानी से बना पाएंगे, हालांकि किसी तरह के नए काम आज शुरू ना करें।

कुंभ
किसी प्रिय मित्र या रिश्तेदार से बातचीत करके मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार में आर्थिक लाभ होगा। सुबह के समय आप शारीरिक रूप से स्वस्थ और मन से खुश रहेंगे। परिजनों और मित्रों के साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है।

मीन
गृहस्थ जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। किसी छोटी यात्रा का आयोजन कर पाएंगे। व्यापार में वृद्धि होगी। विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से शुभ समाचार मिलेंगे। परिश्रम की अपेक्षा फल कम मिलेगा। आज आप अपना जिद्दी व्यवहार छोड़ दें।

शख्सियत

नमस्कार मित्रों हमारे आज के शख्सियत कॉलम की स्टार हैं श्रीमति रेणू गोयल जोकि जीवंत व्यक्तिव के माध्यम से इस समाज को अनेक संदेश देती आ रही हैं। हमेशा ऊर्जा से लबरेज चेहरा मुस्कान बिखेरता, आनन्द लेने में कहीं पीछे नहीं जब मौका लगा खुशियों को ये खोज ही लेती हैं। इनका नाम रेनू गोयल है लेकिन विवाह से पहले नाम रेनू शर्मा था। इनका जन्म अंबाला के मिलिट्री अस्पताल में हुआ था। ये अपने माता-पिता की तीसरी संतान हैं। इनके पिता सेना में अफ़सर थे, उनके अनुशासन व सिद्धांतों का इनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अंडमान-निकोबार, आमला और नसीराबाद आर्मी स्कूल से प्राप्त की। राजस्थान विश्वविद्यालय से इन्होंने बी.ए और एम.ए की पढ़ाई पूरी की। आपकों जानकार हर्ष होगा कि ये राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी रही हैं और इन्हे राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ गाइड पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 2 साल चिनार पब्लिक स्कूल में शिक्षिका के पद पर रही, अब पिछले 30 वर्षों से ये अलवर की सबसे प्रख्यात स्कूल अलवर पब्लिक स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं जहाँ पिछले 14 वर्षों से प्री.प्राइमरी कोऑर्डिनेटर के रूप में सेवाएँ दे रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, ये हमेशा इस बात पर ध्यान देती हैं कि लड़कियों की पढ़ाई-लिखाई का जम्मा उठाया जाए, ताकि वे बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकें। यह काम इन्हे बहुत संतोष और खुशी देता है। ये वामा क्लब से जुड़ी हुई हैं और उसके सभी कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाती हैं। इसके साथ ही इन्होंने पशु कल्याण के लिए भी काफी काम किया है। इनकी शादी इन्ही के सबसे अच्छे मित्र मनोज से हुई। इनका पुत्र भी एक आर्मी अफ़सर है और बिटिया एक मलटीनेशनल कम्पनी से जुड़ी हुई हैं । बेहद सौभागय शाली भी हैं। जीवान्त व्यक्तित्व के जरीए समाज में खुशहाली और तनावमुक्त वातावरण ऐसे ही लोगों के कारण आ सकता है। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्वल भविष्य की कामना करती है। इनका मानना है कि जीवन हमें केवल एक बार मिलता है और सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम इसे दूसरों के साथ बाँटते हैं।

जय हिन्द
रूपक शर्मा

रेणू गोयल
(शिक्षिका, एपीएस)

आज का इतिहास

23 सितंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- रूस और तुर्की के बीच बेलग्रेड शांति समझौते पर 1739 में हस्ताक्षर।
- ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1803 को असाये के युद्ध में मराठा सेना को हराया।
- रूसी युद्धपोत लेफर्ट फिनलैंड की खाड़ी में 1857 को आये भीषण तूफान में गायब हुआ, 826 लोग मारे गए।
- विश्वविख्यात न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रायड 1939 में आज ही के दिन स्वर्गवासी हुए थे।
- बाल विवाह निरोधक विधेयक (शारदा कानून) 1929 में पारित।
- पाकिस्तान ने 1955 को बगदाद समझौता पर हस्ताक्षर किया।
- ब्रिटेन ने 1958 में क्रिसमस द्वीप पर वायुमंडलीय परमाणु परीक्षण किया।
- भारत-पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध विराम का आदेश।
- अब्दुल रजाक बिन हुसैन 1970 में मलेशिया के प्रधानमंत्री बने।
- ब्रितानी नौ सेना के एक युद्धक जहाज में 1976 को घटी दुर्घटना में आठ लोग मारे गए। इंग्लैंड के उत्तर पूर्व में बने एचएमएस ग्लासगो नाम के यह जहाज़ समुद्र में अपना परीक्षण शुरू करने वाला था।
- सोमालिया के संविधान को 1979 में राष्ट्रपति ने मंजूरी दी।
- गल्फ एयर का यह यात्री जहाज 1983 में पकिस्तान के कराची हवाई अड्डे से उड़ा था और पर सवार ज्यादातर यात्री पाकिस्तानी थे। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी और दुबई के बीच इस हवाई जहाज में रखे सामान में विस्फोट हो गया था।
- अमेरिकी कांग्रेस ने 1986 में गुलाब को अमेरिका का राष्ट्रीय फूल चुना।
- यूगोस्लाविया का 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ से निष्कासन।
- ताबा (मिस्र) में 1995 को इस्रायल एवं फ़िलिस्तीनी मुक्ति संगठन के मध्य पश्चिमी तट में फ़िलिस्तीनी स्वशासन के संबंध में समझौता।
- सिडनी ओलम्पिक में 2000 को संयुक्त राज्य अमेरिका की धाविका मैरियन जोन्स ने 100 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक जीता।
- ब्रिटिश व तालिबान सेना के बीच गोलाबारी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2001 को भारत व पाकिस्तान पर से प्रतिबंध हटाये।
- जर्मनी के चांसलर गेरहार्ड श्रीएडर 2002 को पुन: सत्ता में।
- हैती में 2004 को तूफान के बाद आई बाढ़ में कम से कम 1,070 लोग मारे गए।
- पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ़ ने 2006 में भारतीय प्रधानमंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह को वार्ता का निमंत्रण दिया।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 2009 में भारतीय उपग्रह ओशन सैट-2 समेत सात उपग्रह कक्षा में स्थापित किए।

23 सितंबर को जन्मे व्यक्ति

- स्वतंत्रता सेनानी तथा समाज सुधारक यूसुफ़ मेहरअली का जन्म 1903 में हुआ।
- हिन्दी जगत सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह 'दिनकर' का जन्म 1908 में आज ही दिन हुआ था।

विशेष आलेख

डिजिटल दुनिया में क्या देख रहे हैं आपके बच्चे?

बच्चों के लिए साइबर सुरक्षा आधुनिक पेरेंटिंग का एक अनिवार्य हिस्सा

प्रियंका सौरभ

आज के डिजिटल परिदृश्य में, बच्चे तकनीक में डूबे हुए बड़े हो रहे हैं। स्मार्टफ़ोन से लेकर टैबलेट, लैपटॉप और गेमिंग कंसोल तक, इंटरनेट उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। जबकि ऑनलाइन दुनिया अंतहीन शैक्षिक और मनोरंजन के अवसर प्रदान करती है, यह बच्चों को विभिन्न जोखिमों के लिए भी उजागर करती है। डिजिटल क्षेत्र में बच्चों की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा सर्वोपरि है। डिजिटल युग में, बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करना तथा सूचना तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि के साथ, बच्चों को सीखने के अवसर और साइबरबुलिंग, शोषण और आपत्तिजनक सामग्री जैसे जोखिम दोनों का सामना करना पड़ता है। ऑनलाइन सुरक्षा को संतुलित करने के लिए कानूनी ढाँचे, माता-पिता के मार्गदर्शन और प्रौद्योगिकी समाधानों को सम्मिलित करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। कई माता-पिता और बच्चों में पर्याप्त डिजिटल साक्षरता का अभाव है, जिससे सुरक्षित रूप से ऑनलाइन मार्गदर्शन प्रदान करना और संभावित जोखिमों को समझना मुश्किल हो जाता है।

भारत में, केवल 40प्रतिशत व्यक्ति बुनियादी डिजिटल कार्य करने में सक्षम हैं, जिससे बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के प्रयास जटिल हो जाते हैं। बच्चे अक्सर परिवार के सदस्यों के साथ डिवाइस का साझा उपयोग करते हैं, जिससे उनकी ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी और उन्हें विनियमन करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कई ग्रामीण घरों में, साझा फोन के उपयोग से बच्चों द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपयोग की गई गतिविधियों को ट्रैक करना असंभव हो जाता है, जिससे उन्हें साइबरबुलिंग जैसे जोखिमों का सामना करना पड़ता है। कई प्लेटफार्मों पर मजबूत फ़िल्टरिंग तंत्र की कमी के कारण बच्चे अक्सर ऑनलाइन अनुचित सामग्री के संपर्क में आते हैं। यू ट्यूब जैसे प्लेटफार्म के माध्यम से बच्चों द्वारा एडल्ट कंटेंट तक पहुँचने की रिपोर्ट ने मजबूत सुरक्षा जरूरतों की आवश्यकता पर बल दिया है। साइबरबुलिंग और ऑनलाइन शोषण में वृद्धि बच्चों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न करती है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में 3 में से 1 बच्चे ने साइबरबुलिंग का सामना किया है, जिसके उनके स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम देखे गए हैं। सरकारों को माता-पिता और बच्चों दोनों के लिए डिजिटल साक्षरता में सुधार को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रूप से नेविगेट करने में मदद मिल सके। भारत की डिजिटल इंडिया पहल ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता को कवर करने के लिए अपने दायरे का विस्तार कर सकती है। तकनीकी प्लेटफ़ॉर्म को मजबूत अभिभावकीय नियंत्रण की सुविधाएँ विकसित करनी चाहिए जो गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों की बेहतर निगरानी की अनुमति प्रदान करने हैं। कुछ प्लेटफार्मों पर बच्चों को प्रतिबंधित करने से वे वैकल्पिक उपाय ढूंढने लगेंगे, जिससे प्रतिबंध अप्रभावी हो जाएगा। पहचान से संबंधित दस्तावेजों की आवश्यकता वाले आयु सत्यापन सिस्टम गोपनीयता से संबंधित मुद्दे उठाते हैं और अक्सर आवश्यकता से अधिक डेटा एकत्र करते हैं। भारत में, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आयु सत्यापन के लिए आधार के उपयोग ने डेटा के दुरुपयोग के संबंध में चिंताएँ बढ़ा दी हैं। जटिल या कठोर ऑनलाइन नियम अनजाने में हाशिए पर स्थित समुदायों के बच्चों को पहचान से संबंधित दस्तावेजों या डिजिटल संसाधनों तक सीमित पहुँच से वंचित कर सकते हैं। ग्रामीण भारत में, उचित पहचान के बिना बच्चों को सख्त नियमों के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना मुश्किल हो सकता है । टेक प्लेटफ़ॉर्म पर अत्यधिक सख्त नियम लागू करने से नवाचार बाधित हो सकता है और वैश्विक फर्मों के लिए संचालन जटिल हो सकता है। गूगल और मेटा जैसी टेक कंपनियों ने अपने व्यापार मॉडल को

प्रभावित करने वाले जटिल कानूनी ढाँचों पर चिंता व्यक्त की है। पहुँच को प्रतिबंधित करने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने से डिजिटल युग में बच्चों के शैक्षिक अवसरों और कौशल विकास में बाधा आ सकती है।अध्ययनों से पता चलता है कि डिजिटल लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म तक बच्चों की पहुँच उनके कौशल और रोजगार क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यू ट्यूब किड्स जैसे प्लेटफॉर्म स्क्रीन टाइम को मैनेज करने और कंटेंट को प्रतिबंधित करने के लिए कस्टमाइज करने योग्य पैरेंटल कंट्रोल सैटिंग्स प्रदान करते हैं। यूके के आयु-उपयुक्त डिज़ाइन कोड जैसे कानूनों को अपनाने से यह सुनिश्चित होगा कि तकनीकी प्लेटफ़ॉर्म बेहतर सुरक्षा सुविधाओं के साथ बच्चों के अनुकूल डिजिटल वातावरण को विकसित करें। भारत में भी इसी प्रकार के दिशा-निर्देश लागू किये जा सकते हैं, जिसके तहत तकनीकी प्लेटफॉर्म को अलग-अलग आयु समूहों के लिए सुविधाओं को संशोधित करने की आवश्यकता होगी। स्कूलों को बच्चों को डिजिटल स्पेस में स्वयं को सुरक्षित रखने के तरीके सिखाने के लिए पाठ्यक्रम में ऑनलाइन सुरक्षा शिक्षा को शामिल करना चाहिए। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली पाठ्यक्रम में ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल जिम्मेदारी के प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। सरकारों, तकनीकी कंपनियों और नागरिक समाज को बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, साथ ही सूचना तक उनकी पहुँच का अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए । भारतीय शिक्षा मंत्रालय और तकनीकी प्लेटफ़ॉर्म के बीच सहयोग से व्यापक बाल सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जा सकते हैं। डिजिटल युग में, ऑनलाइन सुरक्षा और बच्चों के सूचना तक पहुँच के अधिकार के बीच संतुलन बनाना एक जटिल चुनौती बनी हुई है।

सहयोगात्मक प्रयासों, डिजिटल साक्षरता में सुधार और आयु-उपयुक्त मजबूत विनियमों को लागू कर , बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बेहतर तरीके से सुरक्षित किया जा सकता है। एक समग्र दृष्टिकोण जिसमें माता-पिता, शिक्षकों, सरकारों और तकनीकी प्लेटफार्मों शामिल हो से वैश्विक स्तर पर बच्चों के लिए अधिक सुरक्षित और समावेशी डिजिटल स्थान तैयार होंगे। बच्चों के लिए साइबर सुरक्षा आधुनिक पेरेंटिंग का एक अनिवार्य हिस्सा है। इन तकनीकों को लागू करके, उपयुक्त सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके, और फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट के लाभों का लाभ उठाकर, माता-पिता एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बना सकते हैं जहाँ उनके बच्चे डिजिटल दुनिया से जुड़े जोखिमों को कम करते हुए खोज, सीख और मौज-मस्ती कर सकते हैं। आपके बच्चे की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खुला संवाद और निरंतर शिक्षा आवश्यक है। याद रखें कि सक्रिय कदमों के साथ, आप अपने बच्चों को डिजिटल परिदृश्य को जिम्मेदारी और आत्मविश्वास से नेविगेट करने के लिए सशक्त बना सकते हैं।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,इमीदपुरा रोड खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतीक्षा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान"। प्रधान संपादक-राम बिलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com "पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

एकसाथ चुनाव बड़ी चुनौती

एकसाथ चुनाव भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में बड़ी चुनौती है। केन्द्रीय कैबिनेट ने 'एक देश एक चुनाव' का महत्वाकांक्षी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इसका उद्देश्य लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, शहरी निकायों तथा पंचायतों के चुनाव एकसाथ कराना है। यह महत्वपूर्ण परिवर्तन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुतियों पर आधारित है जिसने इस प्रस्ताव पर 'पूर्ण सहमति' प्रकट की थी। मोदी सरकार इस पहल को संसद में पेश करने की ओर बढ़ रही है, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह योजना संभव है और हमारी वर्तमान स्थिति क्या है? मुख्य रूप से 'एक देश एक चुनाव' लोकसभा, राज्य विधानसभाओं तथा स्थानीय निकायों के चुनाव एकसाथ कराने पर केन्द्रित है। यह व्यवस्था भारत में देश के पहले आम चुनाव 1951-52 से लेकर 1967 तक मानक व्यवहार थी। लेकिन बाद में 1960 के दशकांत में कुछ राज्य सरकारों और लोकसभा के समय से पूर्व भंग होने के कारण एकसाथ चुनाव की लय टूट गई। ऐसे में 'एक देश एक चुनाव' का क्रियान्वयन करने की तुलना में कहना ज्यादा आसान है। इसका कारण वर्तमान संवैधानिक प्राविधान हैं जो सदन में बहुमत समाप्त होने पर राज्य सरकारों या केन्द्र सरकार को भंग करने की अनुमति देते हैं।

एकसाथ चुनाव व्यवस्था पर वापस लौटने के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तनों और 'लाजिस्टिक नियोजन' की जरूरत पड़ेगी। कोविंद समिति द्वारा मार्च में पेश रिपोर्ट में एकसाथ चुनाव के लिए समर्थन रेखांकित करते हुए कहा गया है कि इसका समर्थन 32 राजनीतिक पार्टियों तथा न्यायपालिका के प्रमुख व्यक्तियों ने किया है। 'एक देश एक चुनाव' को यथार्थ बनाने के लिए मोदी सरकार को अनेक विधायी बाधाओं से निपटना होगा। संसद को दो महत्वपूर्ण विधेयक पास करने होंगे जिनमें से एक का संबंध लोकसभा व राज्य विधानसभा चुनावों से तथा दूसरे का नगरपालिका व पंचायत चुनावों से है। विधायिकाओं के कार्यकाल और उनको भंग करने तथा राष्ट्रपति शासन के बारे में संविधान संशोधन जरूरी हैं। संसद की वर्तमान संरचना में यह काम कठिन लगता है। हालांकि, भाजपा सरकार को बहुमत प्राप्त है, पर उसके पास दो तिहाई बहुमत नहीं है, इसलिए संविधान संशोधनों के लिए राज्यसभा में उसे 52 तथा लोकसभा में 72 वोटों की कमी पड़ेगी। ऐसे में विपक्षी पार्टियों का समर्थन महत्वपूर्ण होगा, पर विपक्ष का प्रतिरोध देखते हुए यह कठिन होगा। संसदीय स्वीकृति के साथ ही दूसरे विधेयक को कम से कम आधे राज्यों का समर्थन प्राप्त करना होगा। वर्तमान समय में भाजपा और उसके सहयोगियों का 19 राज्यों पर नियंत्रण है। इसका अर्थ है कि विपक्ष के विरोध के बावजूद यह उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। 'एक देश एक चुनाव' के पैरोकारों का कहना है कि इससे मतदाताओं में अनिच्छा कम होगी तथा मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। सरकार का दावा है कि चुनावों की संख्या कम होने से सुरक्षा बलों की तैनाती घटेगी, ईवीएम का खर्च घटेगा तथा राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार खर्च में बचत कर सकेंगी। लेकिन विपक्ष को इससे राजनीतिक सत्ता पर कब्जे तथा संविधान के उल्लंघन का भय है। इस आशंका का जवाब है कि देश में 1967 तक एकसाथ चुनाव की व्यवस्था सुचारु रूप से जारी थी। एकसाथ चुनाव से प्रशासन देश के विकास के दृष्टिकोण से दीर्घकालीन निर्णय लेने में सफल होगा, 'आदर्श आचार संहिता' से उसके कामकाज में बाधा नहीं पड़ेगी तथा राजनीतिक दलों पर 'लोकरंजक नीतियां' अपनाने का दबाव कम होगा। देखना होगा कि सरकार इस पर व्यापकतम सहमति बनाने में कहां तक सफल होगी।

भारत-बांग्लादेश संबंधों में गिरावट

भारत द्वारा अच्छे संबंध बनाए रखने के प्रयासों के बावजूद बांग्लादेश की कट्टरपंथी प्रभुत्व वाली अंतरिम सरकार में बढ़ती भारत-विरोधी भावनायें बड़ी चुनौती बन गई है।

हिरण्यमय कार्लेकर
(लेखक, द पायनियर के सलाहकार संपादक हैं)

कटु तथ्य यह है कि भारत चाहे जितने प्रयास करे, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ उसके अच्छे संबंध संभव नहीं हैं। यह बहुत से ऐसे लोगों के लिए आश्चर्यजनक है जिनका विश्वास था कि प्रधानमंत्री पद के समान सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस न भारत से घृणा करने वाले हैं और न वे कट्टरपंथी इस्लामवादी हैं। उनको ऐसा व्यक्ति माना जाता है जिनके साथ कामकाजी संबंध बनाए रखे जा सकते हैं। यदि इस आंकलन के साथ विश्वास किया जाए कि वे हमारे देश के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं तो भी समस्या उन लोगों के साथ है जिनका अंतरिम सरकार में प्रभुत्व है।

इनमें छात्र नेता तथा शेख हसीना का तख्तापलट के जिम्मेदार 'एंटी-डिस्क्रिमनेटरी स्टूडेंट्स मूवमेंट'-एडीएसएम के समन्वयक शामिल हैं। कहा जाता है कि उन्होंने मुहम्मद यूनुस को वर्तमान स्थिति में पदोन्नत किया है और वे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी-बीएनपी की मांग मानते हैं। इसके साथ ही सेवानिवृत्त ले.जन. जहांगीर आलम चौधरी को सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर शखावत हुसेन के स्थान पर गृह मंत्रालय का सलाहकार बनाया गया है क्योंकि उनको 'अवामी-समर्थक' माना जाता था। ब्रिगेडियर जनरल हुसेन को टेक्सटाइल एवं जूट मंत्रालय दिया गया है।

वर्तमान समय में अधिकांश समन्वयक कट्टर रूप से भारत-विरोधी हैं और उन्होंने अपने व्यवहार से इसे सिद्ध किया है। बांग्लादेश में अगस्त, 2024 में पूर्वी जिलों में आई बाढ़ की जिम्मेदारी जिस तरह भारत पर डाली गई, इससे स्पष्ट होता है कि वे भारत से घृणा करते हैं। भारत पर बाढ़ की जिम्मेदारी डालते हुए कहा गया कि बांग्लादेश में आने वाली गुमटी नदी पर स्थित डंबर बांध के स्लूज गेट बांग्लादेश के अधिकारियों को बिना चेतावनी दिए खोल दिए गए जिससे उनको स्थितियों से निपटने की तैयारी का मौका नहीं मिला। लोगों ने इसके बाद भारत-विरोधी रैलियां निकालीं तथा उसे अनेक प्रकार की धमकियां दी गईं।

22 अगस्त, 2024 को 'द डेली स्टार' में 'अचानक बाढ़ के लिए भारत को दोषी ठहराने वाले छात्रों का प्रदर्शन' शीर्षक से खबर दी गई कि अनेक विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन, रैलियां तथा मशाल जुलूस निकाल कर भारत को अचानक बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और 'भारत का हमला रोको' जैसे नारे लगाए गए। रिपोर्ट में समन्वयक गुलाम किबरिया चौधरी मिशू को यह कहते हुए बताया गया कि 'पिछले 53 साल से भारत बांग्लादेश को अनेक तरीकों से परेशान कर रहा है।' बांग्लादेश के अधिकांश महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में ऐसे ही प्रदर्शन और रैलियां की गईं जिनमें भारत के खिलाफ ऐसे ही नारे लगा कर जहर उगला गया।

22 अगस्त, 2024 को 'द डेली सन' में 'ढाका विश्वविद्यालय में हुए प्रदर्शन में अचानक बाढ़ के लिए भारत जिम्मेदार' शीर्षक से प्रकाशित खबर में एडीएसएम के एक समन्वयक हसीब अल इस्लाम के हवाले से अन्य बातों के साथ ही यह भी कहा गया कि 'दिल्ली अपना प्रभुत्व और आक्रमण भूल जाओ। फासिस्ट हसीना का समय बीत गया।' 22 अगस्त, 2024 को 'द डेली स्टार' में 'नाहीद ने कहा, भारत ने बांध खोल कर अमानवीयता दिखाई' शीर्षक से प्रकाशित खबर में एक समन्वयक व सूचना एवं प्रसारण समेत अनेक मामलों के सलाहकार मुहम्मद नाहीद इस्लाम ने सलाहकार परिषद की बैठक के अंत में ढाका में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 'हम ऊपर से पानी आते और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा करते देख सकते हैं। भारत ने बिना पूर्व-चेतावनी के बांध खोल कर अमानवीयता और असहयोग प्रदर्शित किया है।' उन्होंने कहा, 'हम प्रार्थना करते और उम्मीद करते हैं कि भारत जल्द ही बांग्लादेश की जनता के खिलाफ इस प्रकार की नीति छोड़ देगा।

हमें ऐसा समाधान खोजना होगा कि हम भारत और बांग्लादेश के लोगों को ऐसी प्राकृतिक विभीषिका से बचा सकें।' इस कथन में दूसरा वाक्य भारत के साथ बिजनेस करने का धोखाधड़ी वाला प्रयास स्पष्ट करता है। यह उनके इस कथन से भी स्पष्ट है कि 'बांग्लादेश की जनता और छात्र भारत की इस नीति से गुस्सा हैं।' उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के लोग लंबे समय से अपने हिस्से के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यानी भारत इसे देने से इनकार कर रहा है।

इस मामले पर भारत ने बताया कि बाढ़ का कारण भारत के सटे क्षेत्रों में अभूतपूर्व मूसलाधार बारिश है जिससे पूर्वी बांग्लादेश प्रभावित हुआ है। इसके बाद से बांग्लादेश के छात्र 'क्रांतिकारियों' की ओर से बाढ़ संबंधी कोई भारत-विरोधी घोषणा सुनने में नहीं आई। लेकिन उन्होंने जो कहा और किया, उससे दो चीजों का संकेत मिलता है। पहला, भारत के खिलाफ गहरे तक व्याप्त घृणा है जो अचानक भड़काऊ बयानों से फूट पड़ती है और इसका तथ्यों व सही सूचनाओं से कोई संबंध नहीं है। नाहीद इस्लाम का उपरोक्त भड़काऊ बयान इसका एक उदाहरण है। यह खासकर इसलिए भी निन्दनीय है क्योंकि सलाहकार होने के नाते उनकी घोषणा पर सरकार की मुहर मानी जाती है।

दूसरा, रैलियों और प्रदर्शनों से स्पष्ट होता है कि कार्रवाइयों के माध्यम से भारत-विरोधी भावनायें अभिव्यक्त करने वाली कोई ढांचागत संरचना है अथवा वह एडीएसएम द्वारा भारत को निन्दा करने वाली लामबंदी व्यवस्था पर लगाम लगाने की इच्छा नहीं रखती है या इसमें सक्षम नहीं है। दूसरे शब्दों में इससे यह सोच स्पष्ट होती है कि वह अवसर मिलते ही भारत की निन्दा करने का मौका खोजती है। इस भावना को समाप्त करना बहुत कठिन है। वैसे भी हर हाल में सलाहकार परिषद की वर्तमान संरचना को देखते हुए इस सोच को समाप्त करने के गंभीर प्रयास की उम्मीद नहीं है क्योंकि वह भारत से घृणा करने वाले लोगों से भरी पड़ी है।

गृह मामलों के सलाहकार ले.जन. जहांगीर आलम चौधरी का मामला उल्लेखनीय है। उनकी घोर भारत-विरोधी भावना कई बार सामने आई है। मेजर जनरल के रूप में वे बांग्लादेश राइफल्स के महानिदेशक थे। तत्कालीन सीमा सुरक्षा बल-बीएसएफ के महानिदेशक अजय राज शर्मा के साथ वार्ता के लिए भारत आ कर उनहोंने 28 सितंबर, 2004 को मजाक उड़ाते हुए उस विस्तृत सूचना को खारिज कर दिया था जो भरत ने उनको भारत के पूर्वोत्तर से सटे बांग्लादेश में भारत के अलगाववादी विद्रोही समूहों के शिविरों के बारे में दी थी।

उन्होंने कहा था, 'बांग्लादेश में एक भी शिविर नहीं है। हमने बीएसएफ की सूची में दिए गए शिविरों का स्थान देखा है। इनमें से कुछ पते हमारे छावनी क्षेत्रों और मुख्यालयों के थे, तथा कुछ पते तो बंगाल की खाड़ी के थे।' इसी यात्रा में उन्होंने भारत में घुसने वाले अवैध बांग्लादेशियों के बारे में कहा था, 'बांग्लादेश से भारत लोग क्यों आएंगे? आपकी आर्थिक स्थिति बांग्लादेश से बेहतर नहीं है। बांग्लादेश में 50,000 भारतीय हैं जो वहां अवैध रूप से गए हैं।' उन्होंने यह भी कहा कि यदि भारत की अर्थव्यवस्था बांग्लादेश से बेहतर होती तो 'आप मध्यपूर्व व अरब देशों में काम करने न जाते।'

धार्मिक मामलों के सलाहकार एएफएम खालिद हुसेन 'हिफाजते इस्लाम बांग्लादेश'-हिफाजत के नायबे अमीर तथा 'बांग्लादेश इस्लामी आंदोलन' के सलाहकार हैं। ये दोनों घोर भारत-विरोधी हैं। 26 मार्च, 2024 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ पर हुए आयोजन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ढाका यात्रा के अवसर पर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में हिफाजत के समर्थकों और सुरक्षा बलों तथा अवामी लीग समर्थकों के बीच टकराव में 13 लोग मारे गए तथा अनेक अन्य घायल हुए थे। मुख्य सलाहकार मुहम्मद युनुस ने 31 अगस्त, 2024 को हिफाजत के नेताओं के साथ मैत्रीपूर्ण बैठक की है।

इन सभी तथ्यों को देखते हुए भारत को अंतरिम सरकार को स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि हम आपके साथ अच्छे संबंध कायम करना चाहते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपको हमें परेशान करने वाले काम नहीं करने चाहिए जैसा आपके देश की पिछली सरकारों ने भारत-विरोधी पूर्वोत्तर भारत के अलगाववादी विद्रोही तत्वों को सुरक्षित स्वर्ग प्रदान कर किए थे। याद रखें कि आप की तुलना में हम आपके लिए ज्यादा बड़ी मुसीबतें पैदा कर सकते हैं।

विचलनों के दौर में ऊबाऊ होता जीवन

शाइनी शर्मा
(लेखिका शिक्षाविद हैं)

ऐसी दुनिया में जहां विकल्प अंतहीन प्रतीत होते हैं, नेटफ्लिक्स शो से लेकर यूट्यूब वीडियो और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म तक, कोई उम्मीद कर सकता है कि बोरियत अतीत की बात होगी। हालाँकि, स्थिति यह है कि अक्सर विपरीत होता है। इतने सारे विकल्पों के साथ, लोग अक्सर जानकारी की मात्रा से अभिभूत हो जाते हैं, जिससे विकल्प का विरोधाभास पैदा होता है।

इस संज्ञानात्मक अधिभार ने निर्णय थकान पैदा करना शुरू कर दिया है, जिससे किसी व्यक्ति के लिए किसी एक गतिविधि का आनंद लेना या उसमें पूरी तरह से शामिल होना मुश्किल हो जाता है। संतुष्ट होने के बजाय, कई लोग अलग-थलग, असंलग्न और अंततः ऊब महसूस करते हैं। सोशल मीडिया और मुख्य रूप से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर शॉर्ट-फॉर्म कंटेंट के उदय ने एक उपभोग पैटर्न को जन्म दिया है जो संक्षिप्त और अक्सर सतही जुड़ाव को प्राथमिकता देता है। इंस्टाग्राम फ़ीड को स्क्रॉल करना, टॉकटॉक देखना या यूट्यूब वीडियो ब्राउज़ करना उपयोगकर्ताओं को क्षणिक विकर्षण प्रदान करता है लेकिन अक्सर गहराई की कमी होती है। स्मार्टफोन और इंटरनेट की सर्वव्यापकता का मतलब है कि लोग लगभग हमेशा ऑन रहते हैं। काम के ईमेल, सोशल मीडिया अपडेट या यहां तक कि टेक्स्ट के लिए लगातार उपलब्ध रहने की अपेक्षा ने उस प्राकृतिक डाउनटाइम को खत्म कर दिया है जो कभी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था।

विडंबना यह है कि, जबकि ये तकनीकें अंतहीन उत्तेजना प्रदान करती हैं, उन्होंने बोरियत के अनुभव को भी बढ़ा दिया है। जुड़े रहने का निरंतर दबाव लोगों को वास्तव में आराम करने या सार्थक गतिविधियों में गहराई से शामिल होने से रोकता है, जिससे वे मानसिक बेचैनी की स्थिति में रहते हैं।

कई नौकरियों में दोहराए जाने वाले कार्य, लंबे समय तक स्क्रीन पर समय बिताना या ऐसे कार्य शामिल होते हैं जिनमें व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना नहीं होती है। यहां तक कि अधिक कार्यभार वाली नौकरियां भी व्यक्तियों को मानसिक रूप से असंतुलित या असंलग्न महसूस करा सकती हैं। एक ऐसी दुनिया में जो पहले से कहीं अधिक जुड़ी हुई और उत्तेजक लगती है, यह कहना विरोधाभासी लग सकता है कि बोरियत तेजी से नई सामान्य होती जा रही है। यह अपेक्षा कि हमें लगातार मनोरंजन या उत्पादक होना चाहिए, ने दुनिया के साथ जुड़ने के हमारे तरीके को बदल दिया है, जिससे विकल्पों और विकर्षणों की प्रचुरता के बावजूद बोरियत की निरंतर भावना पैदा होती है। आज की तेज-तर्रार, हाइपर-कनेक्टेड दुनिया में, कोई यह मान सकता है कि बोरियत एक दुर्लभ घटना होगी। डिजिटल मनोरंजन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और काम की मांग के अंतहीन प्रवाह के साथ, ऊब का विचार लगभग कालभ्रमित लगता है। फिर भी, विडंबना यह है कि कई लोग पहले से कहीं ज्यादा बार ऊब महसूस करने की रिपोर्ट करते हैं। ऊब का अनुभव एक सामयिक, क्षणभंगुर स्थिति से जीवन के एक नियमित हिस्से में बदल गया है। कई मायनों में, ऊब महसूस करना नया सामान्य हो गया है।

सच्चे डाउनटाइम की कमी हमारे ध्यान को खंडित करती है और हमें किसी भी गतिविधि में गहराई से शामिल होने से रोकती है। अपनी नकारात्मक प्रतिष्ठा के बावजूद, ऊब रचनात्मकता और आत्म-खोज के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक हो सकती है। दुनिया के कई महान विचारकों और नवप्रवर्तकों ने अपनी सफलताओं का श्रेय ऊब के दौर को दिया है। जब मन लगातार इनपुट से विचलित नहीं होता है, तो उसके पास घूमने, प्रतिबिंबित करने और नए विचारों के साथ आने की जगह होती है। बोरियत गहन विचार और रचनात्मकता को पनपने के लिए आवश्यक मानसिक विश्राम प्रदान करती है। बोरियत को विराम देने और गहरी मानसिक अवस्थाओं का पता लगाने के अवसर के रूप में फिर से परिभाषित करके, व्यक्ति आधुनिक दुनिया के सतही विकर्षणों से परे पूर्णता पा सकते हैं, अंततः एक अधिक सार्थक और संतुलित जीवन बना सकते हैं।

यह अब केवल एक अस्थायी स्थिति नहीं है, बल्कि आधुनिक जीवन का एक नियमित हिस्सा बन गया है, जो विकल्पों की अधिकता, ध्यान अर्थव्यवस्था और हमेशा उत्पादक होने के दबाव से और भी बढ़ गया है। बोरियत मन की शांति और आत्म-जागरूकता विकसित करने का एक अवसर हो सकता है और भावनाओं से बचना पलायनवाद में बदल सकता है, अक्सर बिना सोचे-समझे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, बिंज-वॉचिंग शो या मनोरंजन के अन्य निष्क्रिय रूपों में संलग्न होने के रूप में। जबकि ये गतिविधियां अल्पकालिक राहत प्रदान करती हैं, वे शायद ही कभी बोरियत के मूल कारण को संबोधित करती हैं और बचने के चक्र को जन्म दे सकती हैं। मानसिक रूप से समृद्ध होने के बजाय, ये विकर्षण असंतोष की भावना को गहरा कर सकते हैं।

आप की बात

आतिशी से उम्मीदें

आम आदमी पार्टी-आप ने दिल्ली में आतिशी को मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित कर राजनीतिक पैंतरेबाजी की है। नए मंत्रिमंडल से दिल्ली में काफी अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। सभी क्षेत्रों में बढ़ी हुई समस्याओं को न्यूनतम करने में नई सरकार को ध्यान लगाना चाहिए। चुनाव समय से पहले कराने में कम एवं रुके हुए विकास कार्यों को पूरा करने में ज्यादा समय, धन और ऊर्जा लगाएं तो राजधानी की धूमिल होती छवि में थोड़ा सुधार आ सकता है। चल रही विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से बजट आवंटन के लिए केंद्र सरकार के साथ तालमेल बेहतर करना चाहिए। राजनीतिक उठापटक में ऊर्जा नष्ट करने की बजाय अनियमितताओं को हटाने एवं घटाने में यदि आतिशी मंत्रिमंडल सफल होता है तो देश एवं प्रदेश का हित होगा। आतिशी के सिर पर कांटों का ताज है। उन्हें स्वयं को केजरीवाल की कठपुतली की छवि से बाहर ला कर दिल्ली के संसाधनों को आम आदमी पार्टी के विस्तार और चुनावी संभावनाओं पर खर्च करने के बजाय दिल्ली की जनता के कल्याण पर खर्च करने का प्रयास करना चाहिए। आतिशी के सामने सुश्री शीला दीक्षित का उदाहरण हैं जिन्होंने केन्द्र में विरोधी सरकार होने के बावजूद दिल्ली के विकास में अभूतपूर्व व असाधारण योगदान दिया था।

युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

अधिकारियों की सोच

पूजा खेडेकर का बर्खास्त किया जाना कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। पूजा खेडेकर ने अपने लिए जिन सुविधाओं की मांग की थी और जिस तरह अपना रुतबा दिखाने का प्रयास किया था, वह अधिकांश बड़े अधिकारियों में व्याप्त सामंती सोच का प्रतीक है। इसीलिए कहा जाता है कि अंग्रेज चले गए मगर अपने रुतबे को यही छोड़ गए जो कि आज भी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के रूप में जनता पर राज कर रहे हैं। कहने को तो हर कर्मचारी जनता का सेवक है। मगर यह सिर्फकहने को ही होता है। मानसिकता मे वह जागीरदार ही होते है। प्रजातंत्र मे किसी के लिए भी वीआईपी संस्कृति की जरूरत नहीं है। मगर यहां तो मामला एकदम उल्टा है। किसी मंत्री से मिलना आसान है मगर किसी कलेक्टर से मिलना मुश्किल। हैरानी की बात यह है कि सबसे बड़े अधिकारी सबसे कम काम करते हैं क्योंकि उनके हर काम के लिए नीचे कर्मचारी नियुक्त होते हैं। इस पूरे ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। वीआईपी रुतबा हटाने के साथ ही बड़े अधिकारियों को दी जाने वाली अधिकांश मुफ्त सेवाएं खत्म की जाना चाहिए। वैसे उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को हर मर्ज की दवा समझना बंद कर सक्षम कर्मचारियों की पदोन्नति होनी चाहिए।

- **विभूति बुपक्या**, खाचरोद

आधुनिक युद्ध तकनीक

लेबनान में इलेक्ट्रॉनिक पेजर में विस्फोट करके इसराइल ने आधुनिक तकनीक के विस्फोटक उपयोग का नमूना पेश कर दिया है। यदि इसके साथ आधुनिकतम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-एआई को जोड़ दिया जाए तो आने वाले समय में स्मार्टफोन है भी छोटा बम बन सकता है। आधुनिक तकनीक का हिंसा, हत्या और युद्ध के लिए ऐसा प्रयोग गंभीर चिन्ता का विषय है। देखा जाए तो वैज्ञानिकों ने दिन-रात एक कर कठोर परिश्रम से मानव हित के लिए जो आविष्कार किये उनसे मानव ने फायदा कम और नुकसान करने में अधिक उपयोग किया है। भविष्य में यह स्थिति पूरी मानवजाति तथा निरपराध लोगों के लिए और अधिक खतरनाक होती जाएगी। इसे नियंत्रित करना और रोकना अब लगभग असंभव हो चुका है।

कोई हैरानी की बात नहीं कि अगले दशक में हम बॉर्डर पर इंसानी सैनिकों के बजाय रोबोट सैनिकों को निगरानी करते और युद्ध करते देखें। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को अपने आविष्कारों के इस हिंसक व मानव-विरोधी प्रयोग पर रोक लगाने के लिए व्यापक विचार-विमर्श कर कदम उठाने चाहिए। यदि ऐसा न हुआ तो युद्धों की लगातार बढ़ती विभीषिका पूरी मानव जाति के लिए ही विनाश का कारण बन सकती है।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

असाधारण चुनाव सुधार

अधिकांश समय चुनावी मोड में रहने वाले देश में बरसों से चुनाव सुधारों की अपेक्षा की जा रही थी। राजग सरकार की कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी देकर लोकतंत्र एवं धन की बर्बादी रोकने की दिशा में सराहनीय पहल की है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। वस्तुस्थिति यह है कि लोकसभा चुनाव के अतिरिक्त विधानसभा चुनावों या स्थानीय निकायों के चुनाव हेतु महीनों सरकारी मशीनरी व्यस्त रहती है। चुनावी वातावरण में मतदाताओं को लुभाने हेतु क्षेत्रीय दलों में होड़ मची रहती है तथा बिना किसी अर्थ नियोजन के राजनीतिक दल जनता को असंभव सुविधाएं देने की गारंटी देने में पीछे नहीं रहते। ऐसे में यदि लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव एक साथ आयोजित होंगे तो अवश्य ही देश के लिए यह सकारात्मक स्थिति होगी। ऐसे में जरूरी है कि सभी राजनीतिक दल एक देश एक चुनाव का समर्थन दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करें। इससे मतदाताओं को भी राहत मिलेगी और बार-बार उनको मतदान पर अपना समय और ऊर्जा बरबाद करने से मुक्ति मिलेगी। इससे मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा।

- **सुधाकर आशावादी**, मेरठ

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते है।

60 प्रतिशत से ज्यादा इलेक्ट्रानिक और संचार उपकरण चीन और उसके ही एक विस्तारित हिस्से हांगकांग से खरीदता है भारत। ऐसे में लेबनान की तरह यदि भारत में भी इन डिवाइसों के माध्यम से हमले की साजिश रची जाती है, तो इसे नियंत्रित करने के समय रहते उपाय करने होंगे।

आजकल

तकनीक आधारित युद्ध के प्रति सतर्कता

लेबनान में 17 सितंबर को हुए पेजर धमाकों में हिजबुल्लाह आतंकी समूह के कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और तीन सौ से अधिक घायल हुए थे। अगले ही दिन वहां बड़ी संख्या में वाकी-टाकी में धमाके हुए जिसमें कम से कम आठ लोगों की मौत हुई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। इन धमाकों के लिए हिजबुल्लाह ने इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि इजरायल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जो भी हो, इस तरह की तकनीक आधारित युद्ध प्रणाली से हर देश को सतर्क रहना होगा

लोकमित्र गौतम
वरिष्ठ पत्रकार

पिछले सप्ताह लेबनान में लगातार दो दिनों तक पेजर और वाकी-टाकी में विस्फोट होने से कई लोग मारे गए और घायल हुए। हालांकि अब तक माना यही जाता है कि पिछले दिनों हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हनिया की हत्या के पीछे इजरायल का हाथ है, लेकिन हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह को अंदेशा था कि हमास के मुख्य बम निर्माता और अल-कस्साम ब्रिगेड की वेस्ट बैंक बटालियन के नेता याह्या अय्याश की तरह हनिया की भी मोबाइल में विस्फोट कराकर ही हत्या की गई है। इसीलिए नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को आदेश दिया था कि वे स्मार्टफोन का उपयोग न करें। वैसे तो पहले ही काफी वर्षों से वे मोबाइल का बहुत कम इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हानिया की मौत के बाद बिलकुल बंद कर दिया था। हिजबुल्लाह के लड़ाके इन दिनों आपस में संपर्क बनाए रखने के लिए केवल पेजर का उपयोग करते थे।

लेकिन 17 सितंबर को हिजबुल्लाह लड़ाकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हजारों पेजर फट गए। इससे 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और तीन सौ से अधिक लोग घायल हो गए। आतंकी विस्फोट की यह एक ऐसी घटना थी, जिसकी इसके पहले कल्पना तक नहीं की गई थी। लेकिन लगता है कि दुनिया को चौंकाकर दहशत में भरने का इजरायल का इरादा अभी पूरा नहीं हुआ था कि अगले दिन लेबनान में हजारों वाकी-टाकी फट गईं। पेजर विस्फोट के बाद जहां दुनिया आतंक से दहल गई थी, वहीं वाकी-टाकी विस्फोट के बाद तो वह सन्न रह गई।

वस्तुतः विश्व में आतंक कायम होने का कारण यह आशंका है कि अब उन्हें भी न कहीं ऐसे ही इलेक्ट्रानिक वारफेयर से दो चार होना पड़े। भले मोसाद ने अपनी इस उच्च तकनीकी ताकत का इस्तेमाल हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के लिए किया हो, लेकिन इन सामान्य इलेक्ट्रानिक उपकरणों को खतरनाक बमों की तरह इस्तेमाल करके इजरायल ने दुनियाभर के आतंकियों को आतंक का वह रास्ता दिखा दिया है कि अब ये छोटी से छोटी और रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग होने वाली इलेक्ट्रानिक डिवाइसेस को बमों के रूप में उपयोग की खौफनाक कल्पनाओं को अंजाम देंगे।

भारत के लिए तो यह आशंका और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हमारे यहां तो आसानी से सबसे खतरनाक बम समझे जाने वाले स्मार्टफोन का उपयोग ही 80 करोड़ से ज्यादा होता है। इनमें से अधिकांश लोग इंटरनेट के भी यूजर हैं।

कहा जा रहा है कि लेबनान में जो पेजर फटे उनमें बहुत मामूली मात्रा में पीईटीएन विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। अगर लेबनान में महज कुछ हजार आयातित इलेक्ट्रानिक डिवाइसेस चेक नहीं कर सकी, तो सोचिए भारत में यह कैसे संभव है जहां हर दिन औसतन पांच लाख विभिन्न इलेक्ट्रानिक डिवाइसेस आयात के जरिये विभिन्न देशों से आती हैं। भारत में संबंधित अथारिटी ही स्वीकारती हैं कि अपने यहां आ रहीं 90 प्रतिशत इलेक्ट्रानिक डिवाइस की चेकिंग ही नहीं होती, तो सोचिए अपने यहां कितनी खतरनाक स्थिति हो सकती है। पिछले कुछ महीनों में जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ बढ़ी है। अब धीरे-धीरे इन सच्चाइयों का राजफाश सामने आ रहा है कि कैसे सुरक्षाबलों और एजेंसियों को चकमा देने के लिए आतंकी यहां भी टेक्नोलाजी और हाइब्रिड वारफेयर का सहारा ले रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों की जांच से पता चला है कि पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए आतंकी इन दिनों धड़ल्ले से अल्पाइन मोबाइल एप का उपयोग कर रहे हैं, जिन्हें आमतौर पर पहाड़ों पर ट्रैकर्स यूज करते हैं। अब ध्यान में आईं ये घटनाएं आशंका पैदा कर रही हैं कि लेबनान की तरह भारत में भी इन साधारण इलेक्ट्रानिक डिवाइसेस से टारगेटेड अटैक किए जा सकते हैं?

सवाल है कि अगर इस तरह की आशंकाओं के तहत भारत में भी आतंकी अटैक की साजिश रची जाती है, तो हम इसे समय रहते नियंत्रित कर सकते हैं? अचानक यह आशंका इसलिए भी उग रही है, क्योंकि हम तो 60 प्रतिशत से ज्यादा इलेक्ट्रानिक और टेलीकाम आइटम चीन और उसके ही एक विस्तारित हिस्से हांगकांग से खरीदते हैं। यही नहीं, हम तो अपनी सारी की सारी एटीएम मशीनें, टरबाइनें, यहां तक कि हमारे महानगरों की शान बनी मेट्रो ट्रेन पूरी की पूरी या इसके ज्यादातर हिस्से भी चीन सहित विभिन्न देशों से खरीदते हैं, तो हमारे यहां स्माल डिवाइसेस से लेकर इन्फ्रास्ट्रक्चर के आधार का भी भारी भरकम बमों की तरह उपयोग किया जा सकता है।

इसलिए हमें बिना देरी किए भारत आने वाले सभी इलेक्ट्रानिक डिवाइसेस की 100 प्रतिशत स्कैनिंग सुनिश्चित करनी होगी, चाहे जितना खर्च बढ़े। अगर सुरक्षित रहना है तो डिवाइसेस चेक नहीं किए जाने का जोखिम नहीं लिया जा सकता। साथ ही मोबाइल, लैपटाप और स्मार्टवाच जैसा हर उस चीज के इस्तेमाल की एक स्मार्ट गाइडलाइन तय करनी होगी और हर नागरिक को उसकी ट्रेनिंग जरूरी करनी होगी। क्योंकि ऐसी सभी डिवाइसेस का बम की तरह इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें बैटरी लगी है और जिसे इंटरनेट के जरिये आपरेट करना संभव हो। इसलिए विदेश से आ रहे हर डिवाइसेस की मानिटरिंग हर हाल में बहुत जरूरी है। याद रखिए हाइब्रिड वारफेयर भारत के लिए लेबनान से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा है। इसलिए लेबनान से सबक लेते हुए हमें इस तरह अलर्ट रहना होगा जैसे ये विस्फोट हमारे यहां ही हुए हों। हाइब्रिड और एसिमिट्रिक वारफेयर परंपरागत तरीके से लड़े जाने वाले युद्ध से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि ऐसे युद्ध में देश का हर नागरिक फौजी की भूमिका में होता है। (ईआरसी)

लेबनान में पेजर और वाकी-टाकी के माध्यम से हुए विस्फोट की घटनाओं के बाद मची अफरातफरी। फाइल

युद्ध के आधुनिक प्रारूप से निपटने की तैयारी

डा. लक्ष्मी शंकर यादव
पूर्व प्राध्यापक, सैन्य विज्ञान विषय

पिछले सप्ताह लेबनान में एक के बाद एक हुए हजारों पेजर धमाकों में 12 लोगों की मौत हो गई तथा ईरान के राजदूत सहित लगभग तीन हजार लोग घायल हो गए। इसके अगले ही दिन लेबनान के अनेक हिस्सों में इलेक्ट्रानिक उपकरणों में विस्फोट की घटनाएं हुईं जिससे अफरा-तफरी मच गई। दूसरी बार के हमलों में वाकी-टाकी और सौर उपकरणों में धमाका हुआ। ये धमाके बेरूत और दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों के घरों में हुए।

अगर पेजर की बात की जाए तो यह आपातकालीन परिस्थितियों में जरूरी संदेशों को तीव्रता के साथ भेजता है। चूंकि यह आकार में छोटा होता है, इसलिए इसे दूर तक भी ले जाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। इनकी खासियत यह होती है कि इनमें कोई फोन नंबर या सिम कार्ड नहीं होता है। इसलिए इनमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहती है। तभी इनकी विश्वसनीयता अधिक होती है। इसके अलावा, इनकी बैटरी ज्यादा समय तक चलती है। वस्तुतः पेजर एक छोटा इलेक्ट्रानिक उपकरण है जिसका उपयोग अल्फान्यूमेरिक या वायस संदेश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पेजर का उपयोग उन इलाकों में भी किया जा सकता है जिन क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क काफी कमजोर होता है। पेजर एनालाग रेडियो तकनीक पर आधारित होते हैं। पेजर डेडिकेटेड रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं तथा ये फ्रीक्वेंसी पर मैसेज प्राप्त करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। पेजर की रेंज प्रयोग में लाई जाने वाली फ्रीक्वेंसी बैंड और पेजिंग नेटवर्क के कवरेज क्षेत्र पर निर्भर करती है। संख्यात्मक पेजर केवल संख्याएं डिस्प्ले करते हैं।

पेजर में विस्फोट के कारणों पर नजर डाली जाए तो इनमें लगाई जाने वाली लिथियम-आयन बैटरी विस्फोट का कारण हो सकती है। लिथियम-आयन बैटरी में थर्मल रनवे नामक एक घटना के कारण विस्फोट होते हैं। यह एक केमिकल चेन रिएक्शन है, जो तब शुरू होता है, जब बैटरी के तापमान में तेजी से परिवर्तन होता है। यह चेन रिएक्शन जब आगे बढ़ता है, तब ऊर्जा के बाहर निकलने के प्रयास में विस्फोट हो जाता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में तीन खुफिया-रक्षा अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि इजरायल ने ही नकली कंपनी बनाकर विस्फोटकों से लैस पेजरों की आपूर्ति हिजबुल्लाह को की थी। यह आपरेशन लगभग दो साल पहले से चल रहा था। हिजबुल्लाह पेजर के प्रयोग पर इसलिए जोर दे रहा था, ताकि कोई जानकारी लीक न हो। इसी बात का फायदा इजरायली खुफिया अधिकारियों ने उठाया और विस्फोटक से लैस पेजर बनाने के लिए यूरोप में नकली कंपनी बना ली। यह कंपनी अंतरराष्ट्रीय पेजर निर्माता के रूप में सामने आई। सही पहचान छिपाने के लिए इसके अलावा दो अन्य फर्जी कंपनियां भी बनाई गईं। बीएसी कंसल्टिंग हंगरी स्थित वह कंपनी थी जो ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो की ओर से पेजर बनाने का ठेका लेती थी। बीएसी ने पेजर बेचने के लिए सामान्य ग्राहकों को शामिल किया। सभी को सामान्य पेजर दिए गए, जबकि हिजबुल्लाह को विस्फोटक से लैस पेजरों की आपूर्ति की गई।

कहा जा सकता है कि अब एक नवीन युद्ध कला ने जन्म ले लिया है। ऐसे में सवाल यही है कि भारत सरकार और हमारे सैन्य नीति नियंता इस घटना से सतर्क हो जाएं और इलेक्ट्रानिक उपकरणों की जो बाहरी देशों से खरीद की जा रही हैं, उन पर लगाम लगाएं या फिर सतर्कतापूर्ण तरीके से खरीदारी करें। भारत में जिस तरह से आतंकवाद का नेटवर्क फैला हुआ है और वे आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उससे चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि यह तकनीक कहीं उनके हाथ लग गई तो बड़ी घटनाएं होने की आशंका बनी रहेगी।

खरी-खरी

पकड़ने की प्राब्लम

पूरन सरमा

सरकार को पकड़ने की बड़ी चुल्ल रहती है, लेकिन अपराधी हैं कि पुलिस से आंख मिचौली खेलते रहते हैं और पकड़ में आते नहीं। एक शहर में घटना होती है और पूरे राज्य की पुलिस अपराधियों को खोजती है, हजारों-लाखों रुपयों का पेट्रोल फूंक दिया जाता है, वायरलेस पर वायरलेस, कंट्रोल रूम से सीधा संपर्क, सतर्कता और भागा-दौड़ी में कमी नहीं, लेकिन परिणाम वही ढाक के तीन पात, खोदते हैं पूरा पर्वत और चूहा भी हाथ नहीं लगता, अपराधियों की बात तो जाने दीजिए।

इस बार भी यही हुआ। स्वयं मुख्यमंत्री कह रहे थे, अपराधी पकड़े गए तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, बस यह पकड़ने की समस्या आड़े आ जाती है, पकड़ने का लफड़ा नहीं होता तो हमारी चौकस पुलिस अपराधियों को छोड़ती नहीं और एक ही पल में सींखचों के भीतर बंद कर देती। चोर चोरी करता है और पकड़ा नहीं जाता और जो पकड़ा जाता है वह चोर नहीं होगा, लेकिन समस्या हल करने के लिए किसी को तो पकड़ना है ही, सो पकड़ लेती है किसी सज्जन-संस्कारवान सीधे-सादे भोले-भाले बेवकूफ आदमी को। संवेदनाओं का नाश इस सीमा तक हुआ है कि दायित्वों तथा कानून की अनदेखी तो सामान्य-सी बात हो गई है। मैं सोचता हूं कि मूल्यों की बात करना अब बेमानी है, पता नहीं मैं कोई भली बात करूं और किसी को बुरी लग जाए तथा पकड़ ले मुझे ही।

यदि पुलिस ने अपराधी से रुपये खा लिए हैं तो बताइए कि भला उसे पकड़ेगी कैसे? अपराधी ने पैसे ही नहीं पकड़ने के लिए दिए हैं, तो हुई न पुलिस की प्राब्लम पर प्राब्लम।

कानून और व्यवस्था में अपराधियों के बचने के लिए 50 रास्ते हैं, और पुलिस सारे रास्ते सुझा देती है, अग्रिम बेल करवा देगी, पीड़ित के बयान गलत दर्ज कर लेगी, इस तरह पकड़ने की प्राब्लम से बचती रहेगी। पुलिस या तो ऊंघने के लिए होती है या निर्दोष को मारने-पीटने के लिए, अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं, अपराध तो उसकी शह और लापरवाही का परिणाम है। ऐसे हालात में जो लोग पुलिस से न्याय की आशा लगाकर चल रहे हैं- वे अपनी आंखें खोल लें तथा बचकर रहें।

पोस्ट

दुनिया भर के स्कूलों में बच्चों के मोबाइल फोन उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। किसी बच्चे को स्कूल में मोबाइल फोन की जरूरत ही नहीं। अगर आपको ऐसी जरूरत महसूस होती है तो यह गलत है। केविन पीटरसन@KP24

श्रीलंकाई चुनाव में मार्क्सवादी दिसानायके की जीत भारत का नया सिरदर्द बन सकती है। वह चीन प्रेमी है। उनकी जीत से भारत विरोधी विचार वालों से सरकार घिर जाएगी! हालांकि उन्हें जल्द समझ आ जाएगा कि महंगाई के नारे पर जीतना और बात है, दिवालिया देश की सरकार चलाना और। शिवकांत@shivkant

अश्विन गेंदबाज के तौर पर स्टुअर्ट ब्राड के समकक्ष रखे जाएंगे और एक आलराउंडर के तौर पर रिचर्ड हेडली के बराबर।
एक्स क्रिकेटर@old_cricketer

भारत बनाम बांग्लादेश का मैच आखिर शेर और बकरी का मुकाबला साबित हुआ। तेज गेंदबाजों की तरह स्पिनर्स भी जोड़ी में शिकार करते हैं। अश्विन और जडेजा की स्पिन जोड़ी विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। भारत की स्पिन मददगार पिचों पर इनके आगे टिकना बड़ी टीमों के लिए भी मुश्किल है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान जीता, पर भारत को हराना नामुमकिन है।
सुशील दोशी@RealSushilDoshi

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या तिरुपति के प्रसाद मामले की सीबीआइ जांच होनी चाहिए?

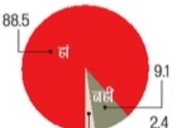

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या भारतीय टीम इस बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने में सफल रहेगी?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

वल्ले से दे सैचरी खूब घुमाई बॉल,
बंगलादेशी टीम का बुरा कर दिया हाल।
बुरा कर दिया हाल जीत ऐसी दिलवाई,
आप रहोगे याद हमेशा अश्विन भाई।
पड़ी न उनकी गेंद टीम बंगला के पल्ले,
भारत जीता मैच हो गई वल्ले-वल्ले!

- ओमप्रकाश तिवारी

चुनाव- उप चुनाव, साख पर बहुत कुछ

हरिशंकर मिश्र
वरिष्ठ समाचार संपादक, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश डायरी

उत्तर प्रदेश में बयानबाजी के लिए बहुत कुछ है और बुलडोजर से लेकर मुठभेड़ एवं भेड़ियों तक पर बयानबाजी जारी है, लेकिन इसके समानांतर राजनीति के लिए भी बहुत कुछ है। प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के लिए राजनीति का पंडाल सजने लगा है तो तय है कि गठबंधन धर्म की परीक्षा एक बार और होगी ही, एवं क्षेत्रीय दलों की सौदेबाजी का दमखम भी देखने को मिलेगा। दूसरी ओर कई राज्यों में भी चुनाव हैं जिसमें सपा अपने राष्ट्रीय दर्जे की संभावनाएं टटोलने में जुट गई है, लेकिन इसमें बहुत कुछ कांग्रेस पर निर्भर है। लोकसभा चुनाव में बसपा को भले ही एक भी सीट पर जीत न मिली हो, लेकिन उपचुनाव और दूसरे राज्यों में हो रहे चुनाव में वह एक बार फिर स्वयं को कसौटी पर कस रही होगी। उसके लिए भी अपना राष्ट्रीय दर्जा बहाल रखने का सवाल अहम है। राजनीति संभावनाओं का खेल है और फिलहाल अवसर सबके लिए खुले हैं।

सबसे पहले बात उप चुनाव की ही करते हैं जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा का प्रश्न है। प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों- मिल्कीपुर, कटेहरी, करहल, कुंदरकी, मीरापुर, खैर, मझवां, गाजियाबाद, फूलपुर व सीसामऊ में उपचुनाव होना है। इनमें पांच सीटें सपा और तीन भाजपा की थीं। एक सीट निषाद पार्टी व एक रालोद के पास थी। एक साथ यदि 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हों तो साख पर बहुत कुछ लग जाता है। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बहुत कुछ खोया है और उपचुनाव ने उसे यह अवसर दे दिया है कि वह अधिक से अधिक सीटें जीतकर 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करे। हालांकि उसकी पहली लड़ाई घटक दलों से ही है। सबसे अधिक दबाव रालोद का है जिसने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा का साथ लेकर मीरापुर और खैर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ा था। मीरापुर में उसे जीत हासिल हुई थी। अब रालोद एनडीए गठबंधन में शामिल है और उप चुनाव में मीरापुर व खैर दोनों सीटें चाहता है। दबाव की राजनीति में कुछ तो हासिल होता ही है और इसलिए संभावना है कि उसे मीरापुर सीट देने को भाजपा तैयार हो जाए। दूसरी ओर निषाद पार्टी भी एक से अधिक सीटों पर लड़ना चाहती है।

योगी आदित्यनाथ। फाइल

अखिलेश यादव। फाइल

निषाद पार्टी ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में राजग गठबंधन के साथ मिलकर मझवां और कटेहरी में चुनाव लड़ा था और एक मझवां सीट जीती थी। भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी को भी एक ही सीट पर लड़ने के लिए राजी करने का प्रयास करेगी।

सपा के लिए भी उपचुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि 2022 में उसने उपचुनाव वाले क्षेत्रों में पांच सीटें हासिल की थीं और इनमें कई सीटों पर उसका प्रभाव है। अब पेच फंसता है कांग्रेस का जो गठबंधन धर्म की आड़ लेकर समाजवादी पार्टी से सीटें लेने का दबाव बनाए हुए है। इसी उद्देश्य से कांग्रेस ने उपचुनाव वाले क्षेत्रों में संविधान सम्मेलन की योजना बना रखी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इस बात को कहते भी हैं कि उपचुनाव में वह अपने प्रत्याशी उतारेंगे। बसपा उपचुनाव पर निगाह रखने के साथ 2027 के चुनाव की ओर देख रही है और इसी वजह से मायावती ने कई नीतिगत निर्णय किए हैं। हर जिले में भाई चारा कमेटियां और सेक्टर प्रणाली खत्म कर मंडलीय व्यवस्था इसी का हिस्सा है।

उपचुनाव से इतर राजनीतिक दलों के बीच अन्य राज्यों के चुनाव को लेकर भी रस्साकसी है, विशेष तौर पर कांग्रेस और सपा के बीच। सपा को उम्मीद थी कि कांग्रेस अपने आधार क्षेत्र में उसके लिए दरवाजे खोलेगी, लेकिन हरियाणा में उसे एक भी सीट नहीं मिली। हरियाणा की मुस्लिम और यादव बहुल 12 विधानसभा सीटों पर सपा ने कांग्रेस से गठबंधन करने का प्रयास किया था। बात पांच और फिर तीन सीट पर आकर टिक गई थी, लेकिन अंततः मायूसी ही हाथ लगी। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 'बात सीट की नहीं, जीत की है' कहकर अपना बचाव जरूर करते हैं, लेकिन उनके निशाने पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में सपा ने 12 प्रत्याशी उतारने का निर्णय लिया है और वहां के विधानसभा चुनाव में जमीन तैयार करने के लिए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय और तीन विधायकों को प्रभारी बनाया है। महाराष्ट्र में सपा का संगठन पहले से ही सक्रिय है और एनसीपी अजित पवार गुट के कई नेताओं के आ जाने से उसे मनोवैज्ञानिक मजबूती हासिल हुई है। मुंबई और ठाणे में उत्तर भारतीय मतदाताओं की संख्या काफी है, इसलिए सपा वहां चुनाव लड़ना चाहती है। इसके साथ ही पार्टी ने जम्मू-कश्मीर के चुनाव में 20 प्रत्याशी उतारकर यह प्रदर्शित किया है कि पार्टी का दर्जा राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए वह कितनी बेकरार है।

मेडिकल प्रवेश परीक्षा

कायम रहे 'नीट' की व्यवस्था

पिछले कुछ वर्षों के दौरान नीट परीक्षा में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। कुछ नेताओं द्वारा इसे भंग करने की बात की जा रही है, परंतु यह सही नहीं होगा, बल्कि इसमें अपेक्षित सुधार होना चाहिए

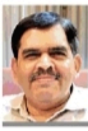

डा. अश्विनी महाजन
पूर्व-प्रोफेसर, पीजीडीएवी कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

अधिकांश छात्र का यह सपना होता है कि स्कूली शिक्षा के बाद वह डाक्टर या इंजीनियर बने या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसका स्वप्न होता है कि आइएएस या अन्य सरकारी सेवाओं की परीक्षा उत्तीर्ण करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। यह भी सही है कि सभी लोग ये परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं कर पाते, लेकिन यदि व्यवस्था में ईमानदारी हो तो कुछ सक्षम विद्यार्थी अवश्य ऐसा कर पाते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा (नीट) में प्रश्न पत्र लीक होने के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। ऐसी भी आवाज उठने लगी है कि नीट की परीक्षा होनी ही नहीं चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि यह मांग परीक्षार्थियों की ओर से नहीं, बल्कि कुछ राजनेताओं की ओर से उठ रही है।

अब सवाल यह है कि यदि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की व्यवस्था को भंग कर दिया जाता है तो उसके स्थान पर कौन सी व्यवस्था लागू होगी? इसमें यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि नीट की व्यवस्था लागू होने से पहले मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं कैसे होती थीं, और उसके क्या गुण-दोष थे? नीट की परीक्षा लागू करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? यदि नीट के स्थान पर पुनः पुरानी व्यवस्था लागू होती है तो उसका मेडिकल कालेजों में उम्मीदवारों के भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है? पेपर लीक की घटना को आधार बनाकर नीट व्यवस्था को भंग करना कितना उचित होगा, इस पर विचार करना जरूरी है।

मेडिकल प्रवेश परीक्षा का इतिहास : नीट लागू होने से पहले अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएससी) द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती थी। जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और अन्य सरकारी प्राधिकरणों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न मेडिकल एवं डेंटल कालेजों के एमबीबीएस एवं बीडीएस डिग्री कोर्सों में प्रवेश हेतु कम से कम 15 प्रतिशत सीटें इस परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की जाती थी। यह सही है कि कुछ बेईमान तत्वों के कारण नीट और यूपीएससी परीक्षाओं में कुछ स्थानों पर पेपर लीक होने के कारण विद्यार्थियों को धक्का लगा है। वैसे निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया हमेशा ही विवाद का विषय रही है। नीट से पहले प्राइवेट मेडिकल संस्थान प्रवेश परीक्षा आयोजित तो करते थे, लेकिन उनमें अधिकांश नामांकन कालेजों को दी जाने वाली राशि के आधार पर होता था।

कुछ अपवादों को छोड़ मोटी फीस के अलावा भारी नकद रकम अलग से चुका कर प्राइवेट मेडिकल कालेजों में प्रवेश मिलता था, तो ऐसे में यह व्यवस्था मेडिकल की पढ़ाई में असमानता का एक बड़ा कारण हुआ करती थी। ऐसे में हालांकि वर्ष 2012 में सरकार द्वारा अलग-अलग प्रांतों और कालेजों के आधार पर विविध प्रकार की परीक्षाओं से निजात पाने के लिए देश में एक साझी परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया गया, जिसके खिलाफ प्राइवेट कालेजों के प्रबंधन ने अदालत में आपत्ति दर्ज की। इस मुकदमे में न्यायालय ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से प्राइवेट मेडिकल कालेजों के प्रबंधन के हित में फैसला देते हुए साझी परीक्षा को यह कहकर निरस्त कर दिया कि यह प्राइवेट कालेजों के अधिकारों का उल्लंघन है।

नई व्यवस्था : केंद्र में नरेन्द्र मोदी सरकार आने के बाद इंडियन मेडिकल काउंसिल और डेंटल काउंसिल आफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 2013 के उसके निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए निवेदन किया। पांच जजों की बेंच ने निर्णय को पलटते हुए 'नीट' परीक्षा को संवैधानिक ठहराते हुए साझी परीक्षा का रास्ता साफ किया। यह अनुभव किया गया कि 'नीट' की साझी परीक्षा के बाद सरकारी कालेजों में ही नहीं, बल्कि प्राइवेट कालेजों में भी योग्यता के आधार पर एमबीबीएस में प्रवेश हो पा रहा है।

लेकिन जबसे 'नीट' की परीक्षा शुरू हुई है, मेडिकल कालेजों में भ्रष्टाचार के माध्यम से कमाई का स्रोत बंद हो चुका है। कुछ समय पहले 'नीट' की परीक्षा में पेपर लीक होने की घटना प्रकाश में आई तो कुछ राजनीतिक पार्टियों ने नीट परीक्षा समाप्त करने की मांग करनी शुरू कर दी है। यह नहीं भूलना चाहिए कि पूरे देश में जितने भी मेडिकल या डेंटल कालेज हैं, उनमें एक बड़ी संख्या राजनेताओं द्वारा स्थापित संस्थानों की है। ऐसे में प्राइवेट मेडिकल कालेजों के प्रबंधक नीट की परीक्षा समाप्त कर मेडिकल प्रवेश को उसी पुराने ढर्रे पर ले जाना चाहते हैं, जहां उन्हें मनमाने तरीके से प्रवेश परीक्षा आयोजित कर भारी रकम कमाने का मौका मिल सके। 'पेपर लीक' की कुछ घटनाओं से प्रभावित होकर इन निहित स्वार्थ वाले लोगों के बहकावे में आकर नीट की परीक्षा को समाप्त करना हमें फिर से उसी अंधे कुएं में धकेल देगा और मेडिकल में प्रवेश फिर से पैसे वाले लोगों का खेल बनकर रह जाएगा।

नीट परीक्षा की विसंगतियों को दूर करते हुए इसे पूर्णतया पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। प्रतीकात्मक

****

राष्ट्रीय सहारा

पटना • सोमवार • 23 सितम्बर • 2024

www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

हर संत का एक अतीत है, और हर पापी का एक भविष्य है।

-ऑस्कर वाइल्ड

नेतृत्व में शामिल हम

अमेरिका के डेलावेयर में चल रही क्वाड नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शिरकत कर रहे हैं। क्वाड यानी चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान शामिल हैं। मोदी ने कहा, हम ऐसे समय बैठक कर रहे हैं, जब दुनिया तनाव और संघर्षों से घिरी हुई है। ऐसे में साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर क्वाड का मिल कर साथ चलना, मानवता के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी कानून पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मामलों के शांतिपूर्ण तरीकों से नतीजे निकालने का समर्थन करते हैं। इस दरम्यान वे अन्य विश्व नेताओं के साथ

द्विपक्षीय बैठकें भी कर रहे हैं। इसके साथ ही न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी भाग लेंगे। क्वाड के गठन को भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबदबे को कम करने वाला संगठन माना जाता है। क्वाड जैसे समूह की जरूरत 2004 में आई सुनामी के बाद महसूस हुई थी। उस वक्त भारत ने अपने पड़ोसी मुल्कों की मदद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर की थी। जापान के तबके प्रधानमंत्री शिंजो आबे को 2007 में इसकी नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। क्वाड नेताओं के साझा बयान में पूर्वी और दक्षिण चीन सागर चिंता जताई गई थी। हैरत की बात है कि इस पर चीन की तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं आई। क्वाड नेताओं का मानना कि वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करेंगे। इसे समावेशी, कुशल, पारदर्शी, लोकतांत्रिक और जवाबदेह बनाने की भी बात की जो स्पष्ट रूप से भारत के पक्ष में नजर आती है। आतंकवाद और हिंसा की आलोचना करते हुए इन नेताओं ने सीमापार आतंक और मुंबई-पठानकोट के आतंकी हमलों की निंदा भी की। इन देशों के साथ रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने और रक्षा, व्यापार, निवेश, शिक्षा एवं अनुसंधान पर सहयोग की चर्चा भी शामिल है। स्पष्ट है कि अमेरिकी रणनीति पाकिस्तान को हाशिए पर करने की नजर आ रही है। चीन और रूस को वे चुनौती की तरह देख रहे हैं, ऐसे में भारत का महत्त्व बढ़ रहा है। भारत-अमेरिका के दरम्यान हो रहा कारोबार दो सौ बिलियन डॉलर तक पहुंचने वाला है। उम्मीद की जा सकती है कि रक्षा, तकनीकी और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर आपदा राहत, साइबर सुरक्षा और टेलीकम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग को उत्सुक मोदी की यह दूरदर्शिता जल्द ही नतीजों के रूप में सामने होगी।

आरोप का सत्यापन जरूरी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निजी आर्थिक लाभ के लालच में हाशिये पर बैठे समाज के कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए बने एससी/एसटी एक्ट के दुरुपयोग को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार को निगरानी तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक तंत्र विकसित नहीं हो जाता, तब तक एफआईआर दर्ज करने से पहले घटना और आरोप का सत्यापन किया जाए ताकि वास्तविक पीड़ित को ही सुरक्षा और मुआवजा मिल सके तथा झूठी शिकायत कर सरकार से मुआवजा लेने वालों के खिलाफ धारा 182 (अब

धारा 214) में कार्यवाही कर दंडित किया जा सके। यह आदेश जस्टिस मंजू रानी चौहान ने बिहारी और दो अन्य की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया। दरअसल, थाना कैला देवी संभल में दर्ज एससी/एसटी एक्ट की एफआईआर पर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। सरकार ने पीड़ित को 75 हजार रुपये मुआवजा दिया। बाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया तो आपराधिक केस रद्द करने के लिए याचिका की गई। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को तलब कर सरकार से लिया मुआवजा वापस करने का आदेश दिया। बेशक, एससी/एसटी वर्गों को जातीय दंभ से भरे लोगों के उत्पीड़न से बचाने की गरज से ऐसे कानून बनाए गए जिनसे इन वर्गों के साथ कोई अन्याय नहीं किया जा सके, लेकिन जैसा कि हर व्यवस्था या प्रावधान के साथ प्रायः होता है, वैसा ही एससी/एसटी एक्ट के मामले में भी कई मामले प्रकाश में ऐसे आए हैं, जब लगा कि इस अधिनियम के तहत किए प्रावधानों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कहीं प्रतिशोधवश को कहीं आर्थिक लालच में झूठी एफआईआर दर्ज कराई जा रही हैं। चूंकि इस एक्ट के प्रावधान कड़े हैं, और पुलिस घटना का सत्यापन किए बिना ही मामले को आगे कार्यवाही करते हुए मामले को अदालत के समक्ष पेश कर देती है। इससे अदालतों में केसों के अंबार में भी इजाफा होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में जो व्यवस्था दी है, वह सही मायने वस्तुस्थिति का प्रकटीकरण है। जरूरी है कि इस कानून में जिस झोल का फायदा निहित स्वार्थी तत्व फायदा उठाने को तत्पर रहते हैं, उन पर रोक लगे और वास्तविक उत्पीड़ित को न्याय मिल सके। अदालत के कहे अनुसार यदि मामले के सत्यापन पर गौर करके एक्ट का दुरुपयोग रोका जा सकता है।

परिधि/ राजीव मंडल

मजबूर न दिखे सरकार

झारखंड आज चर्चा में है। वजह है शिक्षा माफिया का डर। दरअसल, राज्य में 21 और 22 सितम्बर को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के तहत झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय सयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (जेएसएससी सीजीएल) का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए सुबह 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक पूरे झारखंड में इंटरनेट सेवा बंद करने का ऐलान किया।

इंटरनेट के घंटों बंद रहने की खबर से अच्छी-खासी संख्या में लोग परेशान भी दिखे और गुस्सा भी जताया। हालांकि सरकार का इस बावत यही तर्क था कि परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के वास्ते ये कदम उठाया गया है। पूर्व में हुई पेपर लीक के मामलों में देखा गया है कि ज्यादातर पेपर लीक की घटना व्हाट्सएप के जरिए की जाती है। गिरोह के लोग एक संगठन बनाकर इस घटना को अंजाम देते हैं। पहले की गई पेपर लीक की घटना की जांच अभी भी चल ही रही है। ऐसे में सरकार पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रही है। पेपर लीक मामले में अभ्यर्थियों और उनके परिजनों के आक्रोश से सरकार बैकफुट पर है। और यह स्वाभाविक भी है। वर्षों की मेहनत के बाद अगर परीक्षा का पर्चा लीक हो जाए तो उस विद्यार्थी और घरवालों पर क्या बीतती है, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। कई मामलों में तो देखा गया है कि परीक्षार्थी ने इस गम में अपनी जान तक दे दी। वाकई, यह किसी भी सरकार के लिए शर्म की बात है कि वह कोई प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करे और उसका पर्चा पहले ही बेईमानों के हाथों में पहुंच जाए। चूंकि अब ज्यादातर धत्कर्म मोबाइल पर ही अंजाम दिए जाते हैं लिहाजा इस तरह के सख्त फैसले लेना अब सरकार की मजबूरी बन गई है। चाक-चौबंद व्यवस्था की पोल पल भर में खुल जाती है। वैसे, ऐसे फैसले परिपाटी न बने इसके लिए अब सरकार और आम जन सभी को संजीदगी से सोचने की दरकार है। आखिर हम ये बात कब समझेंगे कि बेईमानी से हासिल नौकरी का कोई मोल नहीं होता है। ईमानदारी से तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों की मेहनत सफल हो और अच्छे लोग नौकरी में आएं; इसके लिए अगर चंद घंटे के वास्ते इंटरनेट बंद भी की जाती है तो इसका सम्मान जनता को करना चाहिए। अलबत्ता, शिक्षा माफिया से आमने-सामने की लड़ाई न लड़कर दूसरे आसान तरीकों को अपनाना सरकार के इकबाल के लिए अच्छी बात नहीं है। शिक्षा माफिया को नेस्तनाबूद करना ही मकसद होना चाहिए।

यूरोप क्यों खिलाफ है

तालिबानी मुस्लिम

विनीत नारायण

पिछले कुछ वर्षों से यूरोप की स्थानीय आबादी और बाहर से वहां आकर बसे मुसलमानों के बीच नस्लीय संघर्ष तेज हो गए हैं। ये संघर्ष अब खूनी और विध्वंसकारी भी होने लगे हैं। कई देश मुसलमानों पर सख्त पाबंदियां लगा रहे हैं। उन्हें देश से निकालने की मांग उठ रही है। आतंकवादियों की शरणस्थली बनी उनकी मस्जिदें बुलडोजर से ढहाई जा रही हैं। दाढ़ी रखने और बुर्का पहनने पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं।

यह इसलिए हो रहा है क्योंकि मुसलमान जहां जाकर बसते हैं, वहां शरीयत का अपना कानून चलाना चाहते हैं। वे स्थानीय संस्कृति व धर्म का विरोध करते हैं। अपनी अलग पहचान बना कर रहते हैं। स्थानीय संस्कृति में घुलते-मिलते नहीं हैं। हालांकि सब मुसलमान एक जैसे नहीं होते। पर जो अतिवादी होते हैं, उनका प्रभाव अधिकतर मुसलमानों पर पड़ता है जिससे हर मुसलमान के प्रति नफरत पैदा होने लगती है। यह बात दूसरी है कि इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल जैसे जिन देशों में मुसलमानों के खिलाफ माहौल बना है, ये वो देश हैं जिन्होंने पिछली सदी तक अधिकतर दुनिया को गुलाम बनाकर रखा और उन पर अपनी संस्कृति और धर्म थोपा था। पर आज अपने किए वो घोर पाप उन्हें याद नहीं रहे। पर इसका मतलब यह नहीं कि अब मुसलमान भी वही करें जो उनके पूर्वजों के साथ अंग्रेजों, पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों, डच ने किया था। क्योंकि आज के संदर्भ में मुसलमानों का आचरण अनेक देशों में वाकई चिंता का कारण बन चुका है। उनकी आक्रामकता और पुरातन धर्मांध सोच आधुनिक जीवन के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए समस्या और भी जटिल होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि उनके कट्टरपंथी आचरण का विरोध उनके विरुद्ध खड़े देशों में ही हो रहा हो। मुस्लिम देशों में भी उनके कठमुल्लों की तानाशाही से अमनपसंद अवाम परेशान है।

अफगानिस्तान की महिलाओं को लें। उन पर कठोर पाबंदियों ने इन महिलाओं को मानसिक रूप से कुंठित कर दिया है। वे लगातार मनोरोगों की शिकार हो रही हैं। जब तालिबान ने पिछले महीने सार्वजनिक रूप से महिलाओं की आवाज पर अनिवार्य रूप से प्रतिबंध लगाने वाला कानून पेश किया तो दुनिया हैरान रह गई, लेकिन जो लोग अफगानिस्तान के शासन के अधीन रहते हैं, उन्हें इस घोषणा से कोई आश्चर्य नहीं हुआ।

एक अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी से बात करते हुए वहां रहने वाली एक महिला बताया, 'हर दिन हम एक नये कानून की उम्मीद करते हैं। दुर्भाग्यवश, हर दिन हम महिलाओं के लिए एक नई पाबंदी की उम्मीद करते हैं। हर दिन हम उम्मीद खो रहे हैं।' इस महिला के लिए इस तरह की कार्रवाई अपरिहार्य थी। लेकिन उसके और

उसके जैसी अनेक महिलाओं के लिए ऐसे फैसलों के लिए मानसिक रूप से तैयार होने से उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाला हानिकारक प्रभाव कम नहीं हुआ।

तालिबान द्वारा यह नया प्रतिबंध महिलाओं को सार्वजनिक रूप से गाने, कविता पढ़ने या जोर से पढ़ने से भी रोकता है क्योंकि उनकी आवाज को शरीर का 'अंतरंग' हिस्सा माना जाता है। अगस्त के अंत में लागू किया गया यह तालिबानी आदेश स्वतंत्रता पर कई प्रहारों में से एक है। महिलाओं को अब 'प्रलोभन' से बचने के लिए अपने शरीर को हर समय ऐसे कपड़ों से ढकना चाहिए जो पतले, छोटे या तंग न हों, जिसमें उनके चेहरे को ढकना भी शामिल है। जीवित प्राणियों की तस्वीरें प्रकाशित करना और कंप्यूटर या फोन पर उनकी तस्वीरें या वीडियो देखना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिससे अफगानिस्तान के मीडिया आउटलेट्स का भाग्य खतरे में पड़ गया है। महिलाओं की आवाज रिकॉर्ड करना और फिर उन्हें निजी घरों के बाहर प्रसारित करना भी प्रतिबंधित है। इसका मतलब है कि जिन महिलाओं ने अपने इंटरव्यू रिकॉर्ड किए या वॉयस नोट्स के माध्यम से किसी न्यूज एजेंसी के साथ बात करना चुना तो उन्होंने काफी बड़ा जोखिम उठा कर किया। लेकिन कड़ी सजा की संभावना के बावजूद उन्होंने कहा कि वे चुप रहने को तैयार नहीं हैं। इस एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू के माध्यम से वे चाहती हैं कि दुनिया अफगान महिला के रूप में जीवन की क्रूर, अंधकारमय सच्चाई को जाने।

इस इंटरव्यू में अधिकतर महिलाओं ने अमानवीय सजा के डर से अपना नाम न देने की इच्छा जाहिर की परंतु काबुल की सोदाबा नूरई अनूठी महिला थीं-उन्होंने सजा से बिना डरे अपना नाम लेने की इच्छा की। न्यूज एजेंसी को भेजे वॉइस मैसेज में उन्होंने कहा, 'महिलाओं के लिए सार्वजनिक रूप से बोलने पर प्रतिबंध के बावजूद मैंने आपसे बात करने का फैसला किया क्योंकि मेरा मानना है कि हमारी कहानियों को साझा करना और हमारे संघर्षों के बारे में जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। खुद पहचान जाहिर करना बड़ा जोखिम है, लेकिन मैं इसे लेने को तैयार हूं क्योंकि चुप्पी केवल हमारी पीड़ा को जारी रखने की अनुमति ही देगी। यह नया कानून बेहद चिंताजनक है और इसने महिलाओं के लिए भय और उत्पीड़न का माहौल पैदा कर दिया है। यह हमारी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है, और शिक्षा, कार्य और बुनियादी स्वायत्तता के हमारे अधिकारों को कमजोर करता है।'

उल्लेखनीय है कि सोदाबा नूरई को नौकरी से अगस्त, 2021 में हाथ धोना पड़ा क्योंकि तब वहां तालिबान का राज पुनः स्थापित हुआ और शरीयत कानून के मुताबिक महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए। अब उसे सरकार से प्रति माह 107 डॉलर के बराबर राशि मिलती है, जिसे वह महिलाओं की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त मानती हैं। अफगान महिलाएं चाहती हैं कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को तत्काल एक मजबूत, समन्वित और प्रभावी रणनीति विकसित और लागू करनी चाहिए जो तालिबान पर ये बदलाव लाने के लिए दबाव डाले। इस तालिबानी आदेश से दिखाई देता है कि तालिबान द्वारा किसी एक अधिकार का उल्लंघन अन्य अधिकारों के प्रयोग पर किस तरह से घातक प्रभाव डाल सकता है। कुल मिला कर तालिबान की नीतियां दमन की ऐसी प्रणाली बनाती हैं, जो अफगान महिलाओं और लड़कियों के साथ उनके जीवन के लगभग हर पहलू में भेदभाव करती है। इन दमनकारी आदेशों के खिलाफ विश्व को एक होने की आवश्यकता है।

(लेखक के निजी विचार हैं)

> तालिबान का नया प्रतिबंध महिलाओं को सार्वजनिक रूप से गाने, कविता पढ़ने या जोर से पढ़ने से भी रोकता है क्योंकि उनकी आवाज को शरीर का 'अंतरंग' हिस्सा माना जाता है। अगस्त के अंत में लागू किया गया तालिबानी आदेश महिलाओं की स्वतंत्रता पर कड़ा प्रहार है। महिलाओं को अब 'प्रलोभन' से बचने के लिए अपने शरीर को हर समय ऐसे कपड़ों से ढकना चाहिए जो पतले, छोटे या तंग न हों, जिसमें उनके चेहरे को ढकना भी शामिल है

यह एक बहुत ही खतरनाक आरोप है जो लाखों भक्तों को नाराज कर सकता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने दावों को साबित करना होगा। उन्हें उन कंपनियों के नामों का खुलासा करना चाहिए, जो कार्रवाई वे कर रहे हैं और अन्य ऐसे विवरण देने चाहिए, बजाय इसके कि सिर्फ टूटी-फूटी हिन्दुत्व की धुन बजाएं।

रोहिणी सिंह, पत्रकार
@rohini_sgh

एक बार फिर वही रोना

पर्व | डॉ. रमेश ठाकुर

श्राद्ध पक्ष चल रहा है। इन दिनों गुजरे लोगों को याद करना और उन्हें मनपसंद भोजन बना कर खिलाने की परंपरा निभाई जाती है। मान्यताओं के मुताबिक स्वर्गीय तक भोजन कौओं द्वारा पहुंचाया जाता है। श्राद्धों में कौए परलोकी लोगों के वाहक बनते हैं। पर, कौए इन्हीं दिनों में दूर-दूर तक कहीं नहीं दिखाई पड़ते। श्राद्ध का भोजन लेकर लोग उनके आगमन का लंबा इंतजार करते रहते हैं। लेकिन वो नहीं आते। हों तो ही आए न? हैं ही नहीं? जबकि श्राद्ध में भोजन उन्हीं को ध्यान में रख कर तैयार किया जाता है। जाहिर है जब कौए ही नहीं होंगे, तो श्राद्ध की मान्यताएं भला कैसी पूरी होंगी? हमेशा से होता आया है कि श्राद्ध में पितरों का भोजन जब तक कौए न खाएं, श्राद्ध की मान्यताएं पूरी नहीं होतीं। कौए आएंगे, खाना चुगेंगे और पितरों तक पहुंचाएंगे, लेकिन कौवे नहीं आते? ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी कहीं-कहीं दिख जाते हैं, लेकिन शहरों से कौवे पूरी तरह से गायब हो चुके हैं।

प्राचीन परंपराओं के अनुसार श्राद्धों से कौवों का सीधा संबंध होता है। पौराणिक बातों में यह बात सिद्ध है कि श्राद्धों में जो व्यंजन बनते हैं, उन्हें पितरों तक कौए ही पहुंचाते हैं। श्राद्ध में लोग अपने पितरों को भोजन कराने के लिए घरों के छतों, खेतों, चौक-चौहराओं पर रखते हैं, और कौओं के आने का इंतजार करते हैं। श्राद्ध का खाना कौआ खा ले, तो समझा जाता है कि श्राद्ध की आस्था पूरी हुई। कौओं की संख्या लगातार कम होने से उनकी जबह अब गली-मौहल्ले के आवारा कुत्ते, भेड़-बकरी आदि जानवर श्राद्धों के भोजन पर झपट्टा मारते देखे जाते हैं। कौए नहीं आते तो लोग मजबूरन इन्हीं को कौवो का प्रतिरूप मान कर मन को समझा लेते हैं क्योंकि इसके सिवा कोई विकल्प भी नहीं। दूषित पर्यावरण के चलते विलुप्त होती प्रजातियों में कौए भी शामिल हैं। एक वक्त था, जब घरों के आंगन और मुंडेरों पर कौओं की बहुतायत होती थी। उनकी मधुरई कांव-कांव की आवाजें सुनने को मिलती थीं।

दरअसल, कौए हमेशा से अन्य पक्षियों के मुकाबले तुच्छ माने गए हैं। कौए का शरीर औषधि के तौर पर भी

प्रयुक्त किया जाता है। कौए छोटे-छोटे जीव एवं अनेक प्रकार की गंदगी खाकर भी अपना पेट भर लेते हैं। श्राद्ध पक्ष में इस दुर्लभ पक्षी की भक्ति और विनम्रता से यथाशक्ति भोजन कराने की बात विष्णु पुराण में भी कही गई है। श्राद्धों में कौओं को खाना और पीपल को पानी पिला कर पितरों को तृप्त किया जाता है।

कौओं के संबंध में एक और दिलचस्त बात प्रचलित है। किसी के आगमन की सूचना भी इनकी चहलकदमी से जोड़ी जाती रही है। वक्त वह भी था जब परिवार की महिलाएं शगुन मान कर कौवा को मामा कह कर घर में बुलाया करती थीं, तो कभी उसकी बदलती हुई दिशा में कांव-कांव करने को अपशकुन मानते हुए उड़ जा कहके बला टालती थीं। घर की बहुएं भी कौए के जरिए अपने मायके से किसी के आने का संदेश पाती थीं। कौओं की तरह अब कई और बेजुबान पक्षियों की आबादी घट गई है। इसके पीछे मानवीय हिमाकत प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। पक्षियों के रहने-खाने की सभी जगहों को नष्ट कर दिया गया है। उनके ठिकाने भी कच्चे घर हुआ करते थे, वे भी अब रौंद दिए गए हैं। पेड़ों पर भी इनका निवास होता था, वह भी लगातार काटे जा रहे हैं। समय ज्यादा दूर नहीं, जब श्राद्ध के अलावा किसी भी मौसम में कोई पक्षी नहीं दिखाई दिया करेगा। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के संरक्षक वैज्ञानिक केनेथ रोजेनबर्ग ने कहा भी है कि मोबाइल टावरों के रेडिएशन ने पक्षियों को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई है विशेषकर कौए, तोते, गिद्ध, गोरिया जैसे अद्भुत पक्षियों को। समूची दुनिया में पक्षियों की आबादी लगभग एक तिहाई खत्म हो चुकी है। एक जमाना था, जब कहते थे कि किसी के माथे पर अचानक कोई कौआ आकर बैठ जाए तो अशुभ होता था। उस अशुभता को मिटाने के लिए अपने रिश्तेदारों में उस व्यक्ति के संबंध में मरने की झूठी खबर फैलाई जाती थी। फिर कुछ समय बाद उसी खबर को निराधार किया जाता था। कहा जाता था इस तरह से संभावित विपत्ति टल जाती है।

पहले देखने में आता था कि मरे हुए जानवरों को गिद्ध और कौए खा जाते थे, लेकिन अब उनके न होने से मृत जानवरों के शरीर सड़ते रहते हैं। दुर्गंध दूर-दूर तक फैली रहती है जिससे लोग संक्रमित भी हो जाते हैं। गंदगी को समेटने में गिद्धों, चीलों और कौओं का बड़ा योगदान होता था। कौए अब कितने बचे हैं, और कितने गायब हो गए हैं, इसका सटीक कारण किसी के पास नहीं है। पर्यावरणविद् के अलावा देश के अनगिनत पशु-पक्षी प्रेमी सालों से चिंता जता रहे हैं कि कौआ चील, गिद्ध, गौरैया, सारस के अलावा तमाम दुर्लभ किस्म के भारतीय पक्षी विलुप्त हो रहे हैं। लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं देता। उसी का नतीजा है कि श्राद्धों में कौओं का इंतजार करना पड़ता है।

प्रणिधान | श्रीराम शर्मा आचार्य

प्रणिधान का अर्थ है-धारण करना, स्थापित करना। ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर को धारण करना, ईश्वर को स्थापित करना। परमात्मा हमारे हृदयों में विराजमान है। गीता कहती है-ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। अर्थात हे अर्जुन! ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है। सर्वव्यापक परमात्मा हर एक के रोम-रोम में रम रहा है। फिर भी मनुष्य उसे भूला हुआ है। उसे देखता नहीं, पहचानता तक नहीं और उसकी आज्ञाओं पर ध्यान नहीं देता। कहने को तो लोग ईश्वर को जानते भी हैं, और मानते भी हैं, पर व्यवहार में उसका एक प्रकार से बहिष्कार ही कर देते हैं। पुलिस सर्वव्यापक नहीं है, तो भी उससे जितना डरते हैं उतना ईश्वर से नहीं डरते। अमीरों में उतनी उदारता नहीं होती, तो भी अमीरों या अफसरों का जितना आदर करते हैं, उतना ईश्वर का नहीं करते। स्त्री का प्यार सच्चा और स्थायी नहीं होता, तो भी जितना प्यार अपनी स्त्री से करते हैं उतना ईश्वर से नहीं करते। बेटे के ब्याह में जितना खर्च कर देते हैं, उससे चौथाई भी ईश्वर के निमित्त नहीं लगाते। यदि सच्चाई के साथ देखा जाए तो ईश्वर को एक बहुत ही गौण स्थान दिया जाता है। या तो धन, संपदा, बेटा, पोता, जीत, स्वास्थ्य, विद्या, बुद्धि, स्वर्ग, मुक्ति आदि प्राप्त करने के लिए ईश्वर को टटोलते हैं, या कोई विपत्ति आ जाने पर छुटकारे के लिए उसे पुकारते हैं। अध्यात्म विद्या का जो लोग शोध कर रहे हैं, राजयोग की साधना के लिए यम-नियमों की जो साधना करना चाहते हैं, उन्हें ईश्वर प्रणिधान का तत्त्वज्ञान भली प्रकार समझना होगा और बुद्धिपूर्वक उस पर आरूढ़ होना होगा। योग के आठ अंगों में से द्वितीय अंग नियम का पांचवा नियम ईश्वर पूजा नहीं वरन ईश्वर प्रणिधान है। परमात्मा की हृदय में स्थापना करना, उसे हर घड़ी अपने साथ देखना, रोम-रोम में उसका व्यापकत्व अनुभव करना ईश्वर प्रणिधान का चिह्न है। मंदिर में मूर्ति की स्थापना की जाती है तो पूजा के लिए पूजारी नियत करना पड़ता है जो यथासमय सारी पूजापत्री किया करे। पुजारी अन्य कार्य भी करता है, पर प्रतिमा के भोग, स्नान, शयन, आरती आदि का ध्यान सावधानी के साथ रखता है। ईश्वर प्रणिधान में ईश्वर की प्रतिमा का हृदय में, अन्तःकरण में स्थापित करनी होती है, उसे चौबीस घंटे का साथी बनाना पड़ता है। प्रणिधानी को प्रधानतः ईश्वर में निमग्न रहना पड़ता है।

रीडर्स मेल

इस्राइल की आक्रामकता चिंतनीय

इस्राइल लेबनान में हाल में हुए विस्फोटक उपकरण हमलों के लिए जिम्मेदार है, जो विश्व की स्थिरता के लिए खतरा है। इन हमलों में हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले संचार उपकरणों को निशाना बनाया गया था, लेकिन हमलों की अंधाधुंध प्रकृति ने इस बात को लेकर चिंता बढ़ा दी है कि इन हमलों के लिए कौन जिम्मेदार है, जिनमें 3,000 से अधिक नागरिक घायल हुए हैं। क्या यह एक गुप्त आपूर्ति शृंखला ऑपरेशन था, इसके लक्षित लक्ष्य क्या थे? हमलों की व्यापक प्रकृति, जो चरमपंथी तरीकों से अधिक मिलती-जुलती है, राज्य की कार्रवाई और आतंकवाद के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। क्या इस्राइल की आक्रामकता संघर्ष को व्यापक रंगमंच तक बढ़ाएगी? युद्ध विराम सुनिश्चित करने के लिए दोनों पक्ष कब बातचीत की मेज पर आएंगे?

अंशु भारती, बेगूसराय

कबीर का उल्लेख क्यों

भगवान श्रीराम के विषय में महर्षि वाल्मीकि एवं तुलसीदास तक तो सही है, पर कबीर का उल्लेख क्यूं? बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा 'श्री राम का जीवन हमारे लिए प्रेरणादायी है।' उन्होंने महर्षि वाल्मीकि, तुलसीदास और कबीर के भक्ति भाव पर भी प्रकाश डाला। कबीरदास कहते हैं कि 'पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़'। यदि पत्थर के पूजने से हरी मिलते हैं तो मैं पहाड़ पूज लूंगा। पूरे भारत में अधिकांश लोगों के घरों में प्रभु श्रीराम की मूरत रखी हैं एवं अयोध्या में भी 22 जनवरी, 2024 को प्रभु श्रीराम की मूर्ति स्थापित की गई। इसका तात्पर्य यह है कि पत्थर को क्यों भारत में सभी भारतीय श्री प्रभु राम को भगवान मानते हैं। भारत के विभिन्न मंदिरों में प्रभु श्रीराम की मूर्ति को पूजा जाता है। मुझे नहीं लगता कि यहां कबीरदास का उल्लेख करना उचित है। कबीरदास के कुछ दोहों द्वारा कहीं न कहीं लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई गई है। एक तरफ प्रभु श्रीराम की बात करते हैं, वहीं पत्थर की बात भी करते हैं। क्या यहां कबीर का उल्लेख करना उचित है? है तो किस आधार पर? कैसे? और क्यों?

मिस इंग्लिश, आईआईएमसी, जम्मू

तर्क की कसौटी पर ज्ञान

कर्म का चक्र और वैदिक ज्ञान पर विचार करते हुए एक गहरी आध्यात्मिकता का बोध होता है। इसमें आत्मा के अस्तित्व, उसके पुनर्जन्म और कर्म के प्रभावों पर एक अनूठी दृष्टि प्रस्तुत की गई है परंतु सवाल उठता है कि आज की युवा पीढ़ी इस सोच को किस हद तक स्वीकार कर पा रही है? आज का दौर तर्क और विज्ञान पर आधारित है। लोग हर चीज का प्रमाण चाहते हैं खासकर युवा वर्ग इन वैदिक परंपराओं से लगातार दूर होता जा रहा है। इसका एक प्रमुख कारण है जीवन के हर पहलू को वैज्ञानिक नजरिए से देखने की प्रवृत्ति। आज की पीढ़ी को वैदिक ज्ञान का महत्त्व तब समझ में आ सकता है, जब हम इसे उनके जीवन से जोड़ें। कर्म का सिद्धांत सिखाता है कि हमारे हर कार्य का परिणाम होता है, चाहे वह तत्काल दिखे या बाद में। यह सोचने का समय है कि कैसे इस ज्ञान को आधुनिक जीवन में आत्मसात किया जा सकता है, ताकि यह केवल धार्मिक चर्चा तक सीमित न रहे, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी प्रासंगिक हो। यदि ऐसा होता है, तभी हम वैदिक ज्ञान को प्रासंगिक बना सकेंगे।

अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
● राष्ट्रीयता ● कर्तव्य ● समर्पण

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड प्रेस, मौजा-दरियापुर, पुलिस स्टेशन-शाहपुर, दानापुर, पटना से मुद्रित तथा चतुर्थ तल, सहारा इण्डिया बिहार, बोरिंग रोड क्रासिंग, पटना से प्रकाशित। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी *।

पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, फैक्स : 2535935,2520760 विज्ञापन-3911455/434, प्रसार- 3911451/428

वर्ष - 19, अंक 6430 आर.एन.आई. सं. -बीआईएचएचआईएन/2006/18082 Postal Reg. No. : R-10/NP-50/06-07

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 23 सितंबर, 2024

दैनिक जागरण

आशा भी जीवन में औषधि का काम करती है

बड़े षड्यंत्र का संकेत

कानपुर में रेलवे ट्रैक पर गैस सिलिंडर पाया जाना और पंजाब के बठिंडा में ट्रैक पर सरिया रखा होना महज दुर्योग नहीं हो सकता। ये घटनाएं किसी बड़े षड्यंत्र की ओर संकेत कर रही हैं। इस तरह की घटनाओं के पीछे षड्यंत्र इसलिए भी नजर आता है, क्योंकि इसके पहले भी इसी प्रकार की कई घटनाएं हो चुकी हैं। पिछले दिनों ही सूरत में एक रेलवे ट्रैक की फिश प्लेटें हटी पाई गई थीं और उत्तर प्रदेश में रामपुर में रेलवे ट्रैक पर लोहे का एक खंभा रख दिया गया था। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इसके पूर्व भी इसी तरह के कई मामले राजस्थान, महाराष्ट्र और कुछ अन्य राज्यों में सामने आ चुके हैं। कानपुर में तो ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिनसे यही लगा कि ट्रेनों को पटरी से उतारने की कोशिश की गई थी। एक अनुमान के अनुसार पिछले डेढ़ माह में ऐसी डेढ़ दर्जन घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें ट्रेनों को पटरी से उतारने की अलग-अलग तरह से कोशिश की गई। यह ठीक है कि इस तरह की घटनाओं को रेलवे बोर्ड ने गंभीरता से लिया है और कुछ मामलों की जांच तो रेलवे पुलिस के साथ ही स्थानीय पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी अर्थात एनआइए भी कर रही है, लेकिन यह ठीक नहीं कि अभी तक किसी मामले की तह तक नहीं पहुंचा जा सका है। यदि इन घटनाओं के पीछे के कारणों का शीघ्र पता नहीं लगाया जा सका तो वे तत्व और दुस्साहसी हो सकते हैं जो रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ कर ट्रेनों को पटरी से उतारने की कोशिश करने में लगे हुए हैं।

पटरियों से छेड़छाड़ की घटनाएं नई नहीं हैं, लेकिन आम तौर पर ऐसी घटनाओं को शरारती तत्व अंजाम दिया करते थे, लेकिन अब जिस तरह एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे इस आशंका को बल मिलता है कि इन घटनाओं के पीछे आतंकी तत्व हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि आतंकी अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए शरारती तत्वों का सहारा ले रहे हों। जो भी हो, वस्तुस्थिति सामने आनी ही चाहिए। ट्रेनों के सुरक्षित संचालन को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि अतीत में ट्रेनों को नक्सली और आतंकी संगठन निशाना बनाते रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को अपनी चौकसी बढ़ानी होगी और एक ऐसे माहौल का निर्माण करना होगा जिससे शरारती अथवा आतंकी तत्व ट्रेन को आसान निशाना समझने से बाज आएं। यह कोई अच्छी बात नहीं कि यात्री ट्रेनों में जब-तब पथराव होता रहता है। वंदे भारत ट्रेन को कई बार निशाना बनाया जा चुका है। अब जब यह स्पष्ट है कि ट्रेनों की सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ रहा है तब फिर रेलवे पुलिस, स्थानीय पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ खुफिया एजेंसियों को भी विशेष सजगता का परिचय देना होगा।

लाइफलाइन बनी इंटरनेट

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए राज्य में चार घंटे से अधिक समय तक इंटरनेट सेवाओं को स्थगित कर दिया गया। आज के दौर में सामान्य जीवन से जुड़ी हर चीज इंटरनेट पर आधारित हो गई है। इसके बिना जीवन की कल्पना करना कठिन हो गया है। यात्रा के लिए टिकट का आरक्षण, बच्चों के स्कूल से जुड़े प्रोजेक्ट और चिकित्सा के लिए डाक्टर का परामर्श सब इंटरनेट पर आधारित हो गया है। हालांकि एक खास उद्देश्य से इंटरनेट सेवाएं रोकी गई थीं, लेकिन इसके विकल्प पर भी काम होना चाहिए था। दिन के समय इंटरनेट का बंद होना बैंकिंग सेवाओं के लिए भी परेशानी करने वाला रहा। मोबाइल और एप आधारित सेवाओं की वजह से बैंकिंग की निर्भरता इंटरनेट पर ही रहती है। रविवार को भी इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गईं। आमतौर पर कानून व्यवस्था की समस्या होने पर इंटरनेट सेवाओं को रोका जाता है। राज्य में आए दिन कोई न कोई परीक्षा होती रहती है। ऐसे में अगर इंटरनेट सेवाओं को रोकने का प्रचलन हो गया तो आम जीवन पर गहरा असर पड़ेगा। प्रश्नपत्र लीक को रोकने के लिए संबंधित एजेंसियों को अपने सिस्टम को लीक प्रूफ करने की आवश्यकता है। इसके लिए आमलोगों के जीवन को प्रभावित किया जाना उचित नहीं लगता। झारखंड हाई कोर्ट ने भी इस मामले में दायर याचिका को गंभीरता से लिया है। स्कूली बच्चों के अर्ध वार्षिक परीक्षाओं में भी इंटरनेट सेवाओं के बाधित होने से असर पड़ा है। शिक्षा से लेकर खानपान की जरूरतों पर इस प्रतिबंध ने लोगों को परेशान किया। उम्मीद की जानी चाहिए की राज्य सरकार इससे सबक लेकर आगे से दूसरे विकल्पों की तलाश करेगी।

झारखंड में चार घंटे तक इंटरनेट बंद रहने से कामकाज हुआ प्रभावित, व्यापार समेत आवागमन और चिकित्सा पर पड़ा असर

आयुष्मान भारत का मिशन

जगत प्रकाश नड्डा

स्वस्थ जन ही देश के विकास, उत्पादकता और नवाचार में योगदान कर पाते हैं और आयुष्मान भारत योजना जनस्वास्थ्य सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध हुई है

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी एबी पीएम-जय योजना की छठी वर्षगांठ गर्व का क्षण है। सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में शुरू की गई यह योजना आज विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना में से एक बन चुकी है। यह योजन इस सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि सभी नागरिकों विशेष रूप से सबसे कमजोर वर्गों के लिए समान स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाए। पिछले छह वर्षों में इस योजना ने लाखों जिंदगियों को छुआ है। उन्हें जीवनरक्षक उपचार प्रदान किया है। उनके जीवन में एक नई आशा जगाई है। आयुष्मान भारत की यात्रा प्रमाण है कि एक राष्ट्र जब अपने लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने के लक्ष्य के साथ एकजुट होता है तो क्या कुछ हासिल कर सकता है।

आयुष्मान भारत का मुख्य मिशन यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी भारतीय अपनी वित्तीय स्थिति के कारण स्वास्थ्य सेवा से वंचित न रहे। माध्यमिक और तृतीयक अस्पताल देखभाल को कवर करने के लिए प्रति परिवार पांच लाख रुपये के वार्षिक कवरेज के साथ इस योजना ने आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को देश के कुछ सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा की सुविधा उपलब्ध कराई है। बीते दिनों ही सरकार द्वारा 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के नागरिकों के लिए इस योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है, जो देश के बदलते जनसांख्यिकीय परिदृश्य को देखते हुए महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जैसे कि आशा बहनें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायकों के परिवारों को योजना के दायरे में लाया गया था। आज 55 करोड़ से अधिक लोग इस योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पात्र हैं। इसमें अभी तक 7.5 करोड़ से अधिक सफल उपचार हुए हैं, जिन पर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का खर्च हुआ है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। जो परिवार स्वास्थ्य खर्च के कारण गरीबी के शिकंजे में फंस जाते थे, उनके लिए यह योजना वित्तीय ढाल साबित हो रही है। किसानों से लेकर दैनिक मजदूरों तक के कथन प्रमाण हैं कि यह योजना उन्हें आर्थिक परेशानी से बचा रही है।

इस योजना में उपचार का दायरा भी बहुत व्यापक है, जो 1900 से अधिक चिकित्सा प्रक्रियाओं को कवर करता है। इनमें हार्ट की बाईपास या ज्वाइंट रिप्लेसमेंट जैसी जटिल सर्जरी से लेकर कैंसर और गुर्दे की बीमारियों के उपचार तक शामिल हैं। ये ऐसे उपचार हैं जो पहले तमाम लोगों के लिए पहुंच से बाहर थे, लेकिन अब इस योजना ने उन्हें सुलभ, किफायती और सभी के लिए उपलब्ध बना दिया है। एबी पीएम जय की एक विशेषता इसका एक मजबूत स्वास्थ्य सेवा प्रदाता नेटवर्क तैयार करने की क्षमता रही है। आज, देश के 29,000 से अधिक अस्पताल, जिनमें 13,000 से अधिक निजी अस्पताल शामिल हैं, इस योजना के तहत सूचीबद्ध हैं। यह नेटवर्क ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों तक फैला हुआ है, जिससे सुनिश्चित होता है कि देश के सबसे दूरस्थ हिस्सों में रहने वालों को भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। योजना की अनूठी पोर्टेबिलिटी सुविधा ने यह सुनिश्चित किया है कि लाभार्थी अपने राज्य के अलावा देश भर के अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं।

इस विशाल नेटवर्क को एक मजबूत आइटी बुनियादी ढांचे से लैस किया गया है, जो दावों के निपटान में पारदर्शिता, दक्षता और गति सुनिश्चित करता है। आधार आधारित बायोमीट्रिक सत्यापन और पेपरलेस क्लेम प्रोसेसिंग ने धोखाधड़ी और अक्षमता को काफी हद तक कम किया है। आयुष्मान भारत की सफलता ने स्वास्थ्य सेवा तंत्र के अन्य हिस्सों में भी सुधार को उत्प्रेरित किया है। योजना के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पर जोर ने अस्पतालों को अपने ढांचे और सेवाओं को उन्नत करने के लिए प्रेरित किया है।

एबी पीएम जय के साथ-साथ, सरकार आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी एएएम के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर भी काम कर रही है। अब तक देश में 1.73 लाख से अधिक आरोग्य मंदिर स्थापित किए जा चुके हैं, जो सामान्य बीमारियों और मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर जैसी परिस्थितियों के लिए मुफ्त स्क्रीनिंग, निदान और दवाएं प्रदान कर रहे हैं। कल्याण (वेलनेस) और प्रारंभिक निदान को बढ़ावा देकर हम अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता को कम करने और स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को लंबे समय में और अधिक स्थायी बनाने की उम्मीद करते हैं।

आयुष्मान भारत की उपलब्धियों पर अभिभूत होने के साथ ही हमें भावी चुनौतियों को भी स्वीकार करना चाहिए। योजना का पैमाना विशाल है और इसके साथ इसे लगातार अनुकूलित, परिष्कृत और सुधारने की जिम्मेदारी आती है। हम योजना की पहुंच को बढ़ाने, अस्पतालों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और हर लाभार्थी को प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। भारत की समग्र, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की इस यात्रा को और सुगम बनाने के लिए हम आयुष्मान भारत को मजबूत करना जारी रखेंगे। हम उपचारों की सूची का विस्तार करने, सूचीबद्ध अस्पतालों की संख्या बढ़ाने और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के सफल निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

किसी भी राष्ट्र का स्वास्थ्य उसकी समृद्धि की नींव है। स्वस्थ जनता देश के विकास, उत्पादकता और नवाचार में योगदान करने में सक्षम होती है। आयुष्मान भारत इस स्वस्थ, मजबूत और विकसित भारत की संकल्पना का केंद्र है। इस योजना की सफलता सरकार, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और लोगों के बीच की गई कड़ी मेहनत, समर्पण और सहयोग को दर्शाती है। हम प्रत्येक नागरिक के कल्याण और स्वास्थ्य को लेकर प्रतिबद्ध हैं। इस योजना की छठी वर्षगांठ पर, आइए हम सभी नागरिकों के लिए एक समावेशी, सुलभ और सहानुभूतिपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ भारत के निर्माण की यात्रा को जारी रखेंगे। जय हिंद!

(लेखक केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं)

response@jagran.com

देश में एक बड़े वर्ग का बड़ा सहारा बनकर उभरी आयुष्मान भारत योजना ● फाइल

अविश्वसनीय चीन का मुकाबला

डा. ऋषि गुप्ता

कूटनीति-सैन्य क्षमता से ही भारत चीन को जवाब देने में सफल रहा है, पर बीजिंग के लिए केवल इतना ही पर्याप्त नहीं होगा

वार्ता के जरिये हो रहे शांति के प्रयास। फाइल

गलवन घाटी में वर्ष 2020 में भारतीय-चीनी सैनिकों के बीच सीमा विवाद को लेकर हिंसक झड़प हुई थी। तभी से दोनों पक्ष सैन्य वार्ता के माध्यम से इसको सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। हाल में इसमें थोड़ी प्रगति दिखी। भारतीय और चीनी सेना के आए सकारात्मक बयानों से सीमा पर शांति की उम्मीद जगी है। पिछले चार वर्षों में दोनों देशों की सेनाएं कई बार आमने-सामने आई हैं जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ा। हालांकि इस तनाव की शुरुआत चीन ने की, लेकिन वह भारत को जिम्मेदार ठहराता है। यह उसका पुराना पैंतरा है। चीन ने 1988 के बाद से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने सहित कई सीमा समझौतों का लगातार उल्लंघन किया है और यदि भारत ने प्रतिक्रिया दी है, तो यह अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किया है। बीते दिनों रूस में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के मौके पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। बाद में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने बताया कि 'सीमाई क्षेत्रों में शांति और सौहार्द तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति के लिए आवश्यक है।'

इस संदर्भ में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर का हाल में आया एक वक्तव्य भी काफी महत्वपूर्ण है जिसमें उन्होंने कहा कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सीमा संबंधी विवाद के लगभग 75 प्रतिशत हिस्से का समाधान किया जा चुका है। इस बात की पुष्टि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी की, लेकिन क्या ये संकेत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जून 2020 के पहले की यथास्थिति बहाल होने का संकेत देते हैं? इसका उत्तर नकारात्मक होगा, क्योंकि यदि सही मायनों में देखा जाए तो सीमा विवाद में अब तक किसी तरह का कोई खास सुधार नहीं हुआ है। देपसांग और डेमचोक सीमा विवाद के दो प्रमुख बिंदु हैं, जो अभी भी हल नहीं हुए हैं। फिर नया क्या हुआ है? दरअसल नई बात यह हुई है कि दोनों पक्ष पहली बार कूटनीतिक माध्यम से काम करने तथा सीमा पर विवाद वाले क्षेत्रों में सेना की पूर्ण वापसी के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करने पर सहमत हुए हैं। साथ ही चीन अब इस बात को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर रहा है कि सीमा विवाद के बाद से भारत ने जिस तरह की नीतियां अपनाई हैं वह कारगर साबित हुई हैं। हाल में चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में एस. जयशंकर की आलोचना करते हुए लिखा गया था कि उन्होंने अपनी चीन नीति में जिन कूटनीतिक रणनीतियों को अपनाया वे तिकड़मों से भरी थीं। उनमें न तो जवाहरलाल नेहरू और न ही इंदिरा गांधी की कूटनीति का नैतिक बोध था। भले ही बाद में उसने इस आलेख को हटा दिया, लेकिन यह इस बात का साफ संकेत है कि चीन नेहरू और इंदिरा की चीन नीतियों के साथ सहज था, क्योंकि उस दौर में चीन एक मजबूत स्थिति में रहा, जो चीन को अब मुश्किल लग रहा है।

भारत आज अमेरिका, रूस, चीन के बाद विश्व की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति और विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यही चीन को रास नहीं आ रहा। नीतिगत पटल पर भी भारत की कई पहल चीन को हतप्रभ कर रही हैं। चीन के साथ अपने गहरे व्यापारिक संबंधों के बावजूद भारत अमेरिका जैसे देशों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करके चीन पर अपनी निर्भरता को कम करने में सक्षम रहा है, खासकर सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में। भारत चीनी निवेश पर अपनी उच्च निर्भरता को कम करने के साथ नए निवेशक देशों से जुड़ा है। चीन स्थानीय निवेशकों से भारत में निवेश किए जाने को लेकर भी काफी दबाव में है। यदि चीन इस मुद्दे का समाधान नहीं कर पाया तो इसका असर उसकी आंतरिक राजनीति और आर्थिकी पर होगा। भारत का समान विचारधारा वाले देशों के साथ गठबंधन बनाने का विकल्प भी मजबूत परिणाम देने में सफल रहा है। क्वाड में अमेरिका, भारत, जापान और आस्ट्रेलिया शामिल हैं। यह संगठन चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ प्रभावी है। हालांकि भारत केवल क्वाड जैसे मंचों पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि वह विविध भागीदारों के साथ द्विपक्षीय रूप से जुड़कर भी अपनी क्षमताओं का निर्माण कर रहा है। पदभार संभालने के पहले सौ दिनों से भी कम समय में मोदी प्रशासन ने पूर्वी एशियाई देशों मुख्य रूप से चीन के साथ विवाद का सामना करने वाले देशों जैसे-फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और सिंगापुर के साथ संपर्क स्थापित किया है। इन देशों के साथ व्यापार और रक्षा क्षेत्र में साझेदारियों के साथ भारत आसियान समूह की मजबूती पर भी जोर दे रहा है, जो इन संबंधों को और अधिक समावेशी बनाता है। यह द्विपक्षीय जुड़ाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अगर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होती है तो मुमकिन है कि वह क्वाड जैसे मंच को इतनी प्राथमिकता न दें। ऐसे में आसियान समूह भारत के हिंद-प्रशांत में जुड़ाव को मजबूत रखेगा।

जाहिर है कि भारत ने अपनी कूटनीति और सैन्य क्षमता से चीन को हर मोर्चे पर मजबूती से जवाब देने में सफलता हासिल की है, लेकिन इतने भर से यह मान लेना कि चीन सीमा क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत का और अधिक प्रदर्शन नहीं करने के साथ ही रातोरात सीमा क्षेत्रों में नए गांव बनाकर क्षेत्रीय दावे नहीं करेगा तो यह एक भूल होगी। भारत को चीन की तरफ से किसी भी अप्रत्याशित चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

(लेखक एशिया सोसायटी पालिसी इंस्टीट्यूट, दिल्ली के सहायक निदेशक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

बचपन

बचपन शब्द ही मासूमियत और स्नेह से भरा हुआ है। बचपन मनुष्य के जीवन का प्रारंभिक चरण है, जो लगभग छह से तेरह, चौदह या कभी-कभी और भी दो चार साल तक चलता है। बचपन जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। यह समय उसके सामाजिक संसार को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाता है। यह आयु कोरे पन्नों के समान होती है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। बालक भोलेपन से भरा होता है, उसका लालन-पालन उसके वयस्क जीवन को बहुत प्रभावित करता है। बच्चे मन में किसी भेदभाव बिना जिससे स्नेह मिला उसी के हो जाते हैं। यूं ही नहीं मान्यता है कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। बचपन खेल, मस्ती, खुलकर खिलखिलाना, डांट-डपट को पलभर में भूल जाने से जुड़ा होता है। किसी अनजान बच्चे की किलकारी हमारे होंठों पर मुस्कान लाने के लिए काफी है। यद्यपि कुछ बच्चे इतने भाग्यशाली नहीं होते। उनका बचपन प्रारंभ से ही त्रासदी से भरा होता है। ऐसे बच्चों को छोटी सी मदद भी उन्हें ढेरों खुशियां दे जाती है।

बचपन में इतनी सुंदरता भरी है कि यदा-कदा हमारा मन करता है कि चिंता और द्वेष रहित यह अवस्था यूं ही अनवरत चलती रहे। ऐसा अमृत हर अवस्था में धाराप्रवाह बहता रहे, लेकिन यह संभव नहीं। तो फिर क्यों न किसी भी आयु में हम बचपन के कुछ मनोहर पल चुरा अपनी झोली में भर आनंदविभोर हो लें। हम बचपन की बातें याद कर आनंदित होते हैं, उन्हीं बातों को दोहराते रहना चाहते हैं। ऐसे में थोड़ा सा बचपन अपने भीतर जीवित रखने में कोई हानि नहीं। उनसे थोड़ी सी मासूमियत, निःस्वार्थ भावना अपने में समेट लें। बचपन में लौट पाना तो असंभव है, परंतु बच्चों का साथ ईश्वरीय सुख की अनुभूति कराने के लिए पर्याप्त है। उनके संग तुतलाना, घुटनों के बल चलना, खेलना-कूदना और उनके पवित्र मन का साथी बनना किसी अध्यात्म से कम नहीं।

छाया श्रीवास्तव

भविष्य की जरूरत ई-वाहन

सुनीता मिश्रा

पीएम-ई ड्राइव योजना से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ेगी, जिससे प्रदूषण और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से निपटने में मदद मिलेगी

केंद्र सरकार ने पीएम-ई ड्राइव नाम से एक नई योजना की घोषणा की है। इसमें इलेक्ट्रिक ट्रक, टेंपो और दोपहिया वाहनों को खरीदने पर फेम-1 और फेम-2 की तरह सब्सिडी भी मिलेगी। इसके तहत देशभर के 88,500 स्थानों पर नए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर लोगों में लगातार क्रेज बढ़ रहा है। भारत की सड़कों पर इलेक्ट्रिक रिक्शा समेत बैटरी से चलने वाले वाहनों की संख्या में काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या लाखों में हैं। वर्ष 2020-21 में ई-रिक्शा का पंजीकरण मुश्किल से 78,700 था, जो 2022-23 में बढ़कर लगभग तीन लाख हो गया। इसी तरह पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग चार लाख ई-रिक्शा का पंजीकरण किया गया।

देखा जाए तो ई-रिक्शा हाल के वर्षों में भारत में परिवहन का एक लोकप्रिय साधन बन गए हैं। ये शहरी और ग्रामीण परिवहन जरूरतों को पूरा करते हुए अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी के प्रमुख साधन के रूप में उभरे हैं। पहले जहां आसपास जाने या करीबी शहर जाने के लिए लोगों को आटो या बस के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था, उसे अब इलेक्ट्रिक रिक्शा ने सुगम कर दिया है। दो से चार किलोमीटर की दूरी तय करने में ई-रिक्शा बेहद काम आते हैं। ई-रिक्शा महिलाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ-साथ उन लोगों को भी अपने सपने साकार करने का अवसर दे रहे हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है। बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए भी इलेक्ट्रिक वाहनों को सबसे कारगर माना गया है, लेकिन लोगों को अक्सर इसकी चार्जिंग, पावर और स्पीड को लेकर शिकायत होती है। इलेक्ट्रिक वाहन बहुत शांत होते हैं, जिससे सवारी करने का अनुभव बेहतर होता है।

ज्ञात हो कि वाहनों की कमी के कारण सुदूर और दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोग अपना काम करने के लिए कई किलोमीटर दूर चल कर जाते हैं, जिसके कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं कई महिलाएं नौकरी करना चाहती हैं, लेकिन लंबी दूरी और अधिक किराया लगने की वजह से उन्हें भी समझौता करना पड़ता है और न चाहते हुए भी घर में रहने को मजबूर होना पड़ता है। फिलहाल विकसित देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन जोर पकड़ रहा है। ऐसे में उम्मीद है केंद्र सरकार की पीएम-ई ड्राइव योजना फायदेमंद साबित होगी। इससे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा मिलेगा जिससे प्रदूषण के बढ़ते स्तर और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से निपटने में मदद मिलेगी। यह न केवल भविष्य में कारगर सिद्ध होगा, बल्कि इससे हम लोग स्वच्छ वातावरण में खुलकर सांस भी ले सकेंगे।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

लोकतंत्र में एक साथ चुनाव

'संभव हैं एक साथ चुनाव' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में संजय गुप्त का कहना सही है कि 'एक साथ चुनाव' की अवधारणा सकारात्मक हो सकती है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियां और जमीनी वास्तविकताएं हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। इस विचार को प्रस्तुत करते समय इसके फायदों को लेकर तमाम तर्क दिए जाते हैं कि इससे सरकारी धन की बचत, प्रशासनिक सुगमता और राजनीतिक स्थिरता आएगी। इसमें कोई शक नहीं कि बार-बार होने वाले चुनाव सरकारी नीतियों को बाधित करते हैं और आम जनता पर भी कर का बोझ बढ़ाते हैं, परंतु असली सवाल यह है कि क्या यह व्यवस्था हमारे संघीय ढांचे और विविधतापूर्ण लोकतंत्र के लिए उपयुक्त है? भारत में हर राज्य की अपनी राजनीति, सामाजिक संरचना और विकास की प्राथमिकताएं होती हैं। क्या हम चुनावों को एक साथ कराकर उन विशेष मुद्दों को दबा नहीं देंगे, जो स्थानीय स्तर पर प्रमुख हैं? जैसे महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के चुनावी मुद्दे कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। इस तरह का केंद्रीकरण कहीं जनता की आवाज को नजरअंदाज करने का रास्ता तो नहीं बन जाएगा? चुनाव सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र का उत्सव हैं। एक साथ चुनाव का विचार आकर्षक तो है, लेकिन इसे लागू करने से पहले हमें अपने लोकतांत्रिक ढांचे की विविधता और जमीनी हकीकतों को ध्यान में रखना होगा। इससे जुड़े कानूनी और प्रशासनिक मुद्दों का संतुलित हल निकालना बेहद जरूरी है, ताकि यह विचार महज एक सियासी जुमला न बनकर ठोस सुधार की दिशा में पहला कदम साबित हो सके।

awanishg30@gmail.com

मुफ्त चुनावी घोषणाएं

वर्तमान में राज्यों की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करने से पता चलता है कि देश के सभी राज्यों पर कर्ज की स्थिति बनी हुई है। वर्तमान में पंजाब राज्य पर 3,53,600 करोड़ रुपये का कर्ज है, जो कि देश का सबसे बड़ा कर्जदार राज्य बन चुका है। पंजाब की कुल जीडीपी का 53.30 प्रतिशत कर्ज है, जबकि रिजर्व बैंक के अनुसार यह राज्य की कुल जीडीपी का 30 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही रिजर्व बैंक के अनुसार, हरियाणा पर 2,87,266 करोड़ का कर्ज है, लेकिन कुछ दल चुनाव में बिजली फ्री, महिलाओं को हर महीने नकदी देने का वादा कर रहे हैं। सवाल है कि इन मदों पर खर्च होने वाला पैसा कहां से आएगा? जबकि राज्य की आर्थिक रूप से दयनीय स्थिति बन चुकी है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लाले पड़े हुए हैं, जबकि कर्नाटक में विकास कार्यों की हालत खस्ता है। जनसाधारण को भी सोचना चाहिए कि फ्री चुनावी घोषणाओं से विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाएं तो प्रभावित होती ही हैं साथ में राज्य एवं देश के विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। आज जनसाधारण को फ्री के बजाय ठोस नीतियों की जरूरत है, जिससे रोजगार सृजन, आधुनिक शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें। मुफ्त वाली चुनावी घोषणाएं दिग्भ्रमित करने वाली मृग मरीचिका हैं।

दीपक गौतम, सोनीपत

जम्मू-कश्मीर का संदेश

गत लोकसभा चुनाव में भी कश्मीरी जनता ने बढ़-चढ़ कर वोट दिया था और कुछ संसदीय क्षेत्रों में तो ऐतिहासिक वोटिंग हुई थी। उसी जोश को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने विधानसभा चुनावों के पहले चरण में भी वोटिंग की है। यह कश्मीरी वोटरों की बेचैनी की अभिव्यक्ति है। यह इस बात को और पुख्ता करता है कि लोकतांत्रिक तौर-तरीके से ही जनता की आवाज सुनी जा सकती है और उनकी समस्याओं का हल हो सकता है। कश्मीरी युवा भी यही चाहते हैं कि वे भी देश की मुख्यधारा के साथ जुड़ें और शांति के साथ अपना जीवन गुजर बसर करें। यह एक अच्छी बात है कि पहले चरण के चुनाव बिना किसी हिंसा के संपन्न हुए और आशा करेंगे कि बाकी चरणों में भी शांतिपूर्ण तरीके से ही चुनाव हों।

बाल गोविंद, नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 187

भारत के भूराजनीतिक हित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ पिछली व्यक्तिगत बैठक और उनकी अध्यक्षता वाली क्वाड सालाना शिखर बैठक के दौरान जी 7 देशों के साथ भारत के बढ़ते तालमेल को रेखांकित किया। बाइडन का कार्यकाल आगामी जनवरी में पूरा हो जाएगा। दोनों बैठकों में चीन की बढ़ती होड़ से मुकाबला करने के रास्ते तलाशने के प्रयास किए गए। इसकी पुष्टि बाइडन द्वारा क्वाड नेताओं को दिए हॉट माइक कमेंट से भी होती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन, एशिया-प्रशांत के देशों का इम्तहान ले रहा है। इस संदर्भ में क्वाड नेताओं के साझा विलमिंग्टन घोषणापत्र में न केवल बढ़ी हुई भूराजनीतिक चिंताओं तथा उन्हें हल करने के लिए चुनिंदा पहलों को दर्शाया गया बल्कि इसमें वैश्विक सुरक्षा ढांचे के व्यापक पहलुओं पर संबंधों को गहरा बनाने का एजेंडा भी जारी रखा गया। इसमें स्वास्थ्य सहयोग से लेकर बुनियादी ढांचा क्षेत्र की संयुक्त परियोजनाएं और जलवायु परिवर्तन तक सभी पहलू शामिल थे। इनमें से कई कार्यक्रमों को 2025 में स्पष्ट आकार मिलेगा, जब भारत क्वाड शिखर बैठक की मेजबानी करेगा।

इस संदर्भ में देखें तो प्रमुख परियोजनाओं में से एक है हिंद-प्रशांत में प्रशिक्षण की समुद्री पहल (मैत्री) जो 2022 की समुद्री क्षेत्र जागरूकता परियोजना पर आधारित है। यह साझेदार देशों को उनके विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में गतिविधियों पर नजर रखने की सुविधा देती है। इसमें अतिक्रमण और गैरकानूनी गतिविधियां शामिल हैं। मैत्री का लक्ष्य है इन उपायों का अधिकतम इस्तेमाल करना। अगले वर्ष भारत में इसकी आरंभिक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। मुंबई में भी क्वाड क्षेत्रीय बंदरगाह और परिवहन सम्मेलन आयोजित किया जाएगा ताकि समूह के उन प्रयासों को मजबूती दी जा सके जिनके तहत वह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बंदरगाहों का टिकाऊ और मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करा सकता है। यह ऐसी पहल है, जिसे दक्षिण और पूर्वी चीन सागर के पड़ोसी देशों में चीन के अतिक्रमण को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है। इससे संबंधित संयुक्त वक्तव्य को पढ़ें तो वह गंभीर चिंताओं की बात करता है। संयुक्त वक्तव्य कई अनुच्छेदों में बहुत मजबूती से चीन के सहयोगी उत्तर कोरिया के निरंतर परमाणु हथियार बनाने के प्रयासों की आलोचना करता है। दस्तावेज में सेमीकंडक्टर, कृषि शोध, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष शोध आदि सभी क्षेत्रों का उल्लेख है और क्वाड सहयोग की बढ़ती सार्वभौमिक प्रकृति को रेखांकित किया गया है। दुनिया के गरीब देशों तक भारत की पहुंच को स्वीकार करते हुए वक्तव्य ने यह इरादा प्रकट किया कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के जरिये उसे अधिक समावेशी बनाने का प्रयास करेगा। इसके लिए स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात कही गई। इरादा यह है कि अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों के प्रतिनिधित्व को सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में स्थान दिया जाए। मोदी की यात्रा ने भारत को 14 सदस्यों वाले हिंद प्रशांत आर्थिक समृद्धि ढांचे (आईपीईएफ) के और नजदीक लाने में भी सहायता की। यह पहल क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव से निपटने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2022 में की थी। क्वाड के साझेदार देशों जापान और ऑस्ट्रेलिया के उलट भारत ने 15 सदस्यीय क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसेप) से बाहर रहने का निश्चय किया, जबकि चीन इसका सदस्य है। परंतु उसने आईपीईएफ के चार में से दो स्तंभों – स्वच्छ और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु के अनुकूल प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करना तथा भ्रष्टाचार विरोधी और कर पारदर्शिता के उपायों को मजबूत करना है।

भारत ने फरवरी में आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने का समझौता स्वीकार किया। आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो भारत ने फ्रेमवर्क के पहले स्तंभ व्यापार के क्षेत्र में पर्यवेक्षक रहना तय किया है। इस साझेदारी का भविष्य बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे क्या होते हैं। अगर डॉनल्ड ट्रंप को दूसरा कार्यकाल मिलता है तो आईपीईएफ में गतिरोध आ जाएगा क्योंकि वह धमकी दे चुके हैं कि वह सत्ता में आए तो इस समझौते को नकार देंगे। बहरहाल भारत क्वाड का इकलौता विकासशील साझेदार देश है। उसने क्वाड और आईपीईएफ के साथ स्पष्ट संकेत दिया है कि उसके भूराजनीतिक हित कहां होने चाहिए।

लोकतंत्र में धैर्य पर अमल और उसका महत्त्व

श्रीलंका में बदलाव का सहजता से प्रबंधन किया गया। इसका विपरीत परिदृश्य बांग्लादेश में देखा जा सकता है। बांग्लादेश में गैर राजनीतिक लोगों की एक अनिर्वाचित सरकार स्थापित कर दी गई।

राष्ट्र की बात
शेखर गुप्ता

श्रीलंका में सीमित ढंग से कराए जा रहे चुनाव में वहां के लोग एक नए राष्ट्रपति का चुनाव कर रहे हैं और यह उपयुक्त अवसर है कि हम खुद को यह याद दिलाएं कि महज दो वर्ष पहले वहां जिस तरह की घटनाएं घटी थीं, उसके बाद वहां के लोगों ने कितने परिपक्व और शांतिपूर्ण तरीके से हालात का प्रबंधन किया है। वे अपनी मुख्यधारा की राजनीति के तीन जाने-पहचाने चेहरों के बीच चयन कर रहे हैं और देश में कोई अस्थिरता नहीं है।

यहां एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण सबक निहित है: कई बार देश और समाज उथल-पुथल से गुजरते हैं। इसके परिणामस्वरूप कुछ देश खुद को नष्ट कर लेते हैं तो कुछ और बदलाव, अस्थिरता के चक्र से ही जूझते रहते हैं। जो देश बच जाते हैं और शायद अधिक मजबूत बनकर उभरते हैं उन्हें उनके लोकतांत्रिक धैर्य के लिए सराहा जाना चाहिए जो अक्सर नहीं होता। लोकतांत्रिक धैर्य क्या है और यह कैसे काम करता है?

पहले बात करते हैं श्रीलंका की। जुलाई 2022 में दुनिया ने चकित होकर वे तस्वीरें देखीं जिनमें प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन को लूट रहे थे, वहां से स्मृति चिह्न बटोर रहे थे, स्विमिंग पूल में तैर रहे थे और रील्स बना रहे थे। सरकार हट चुकी थी लेकिन इसके बाद भी ऐसा निर्वात नहीं निर्मित हुआ जहां प्रदर्शनकारी, छात्र नेता, स्वयंसेवी संगठन या दोहरे पासपोर्ट धारक लोग घुसपैठ कर सकें। इसके विपरीत बांग्लादेश के हालात देखिए। उन्होंने अपने शासक को निर्वासित होने पर विवश किया। स्वयंसेवी संगठनों, छात्रों, टेक्नोक्रेट्स और इस्लामिस्ट की एक अनिर्वाचित सरकार ने जगह ले ली। अब वे विदेशों में रह रहे विद्वानों को आमंत्रित कर रहे हैं ताकि देश का नया संविधान लिखा जा सके। सेना के सभी कमीशंड अधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे दी गई हैं और इस प्रकार औपचारिक रूप से शासन में सेना को शामिल कर लिया गया है। इसे पाकिस्तान का हल्का संस्करण कह सकते हैं।

दोनों पड़ोसियों में एक जैसी उथल-पुथल हुई। कैसे एक देश सहजता से बदलाव का प्रबंधन करने में कामयाब रहा जबकि दूसरे ने ऐसा कोई प्रयास भी नहीं किया। इसमें नेपाल को भी शामिल कर लेते हैं। एक जनांदोलन और सशस्त्र माओवादी उपद्रव की बदौलत वहां राजशाही का अंत हुआ। तब से अब तक 16 वर्ष के लोकतांत्रिक शासन में देश में आठ प्रधानमंत्रियों ने 16 छोटे-छोटे कार्यकाल निभाए हैं। परंतु वे अपने लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उनके पास लोकतांत्रिक धैर्य है।

अगर आपके पास इतना धैर्य नहीं होता है तो आप शॉर्ट कट की तलाश करते हैं। बांग्लादेश को देखिए। श्रीलंका का बदलाव सहज रहा और वहां जाने पहचाने राजनीतिक चेहरे देखने को मिले। उनमें 75 वर्षीय रनिल विक्रमसिंघे भी शामिल थे जो मौजूदा पदधारी और उम्मीदवार हैं। श्रीलंका ने किसी को बाहर से आयात नहीं किया। न तो किसी पड़ोसी को और न ही किसी वैश्विक फाउंडेशन को जिसे उम्मीद हो कि वह तीसरी दुनिया के गरीब देशों को लोकतांत्रिक बना सकता है। यही वजह है कि विक्रमसिंघे जीतें या हारें, हमारी दलील मजबूत ही होगी।

अपनी राजनीति और स्थिति को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने उस समय पद संभाला जब निर्वात का संकट मंडरा रहा था। अब यह लोगों पर है कि वे अपना नया राष्ट्रपति चुनें और वह इसे स्वीकार करेंगे। वह 28 की आयु में मंत्री बन गए थे और कई बार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रह चुके हैं। 2022 में प्रदर्शनकारी बदलाव चाहते थे। अगर विक्रमसिंघे किसी चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वह है निरंतरता। उन्हें एक विश्वसनीय विकल्प माना गया क्योंकि वह लोकतांत्रिक हैं।

अब सवाल पर वापस आते हैं: कुछ देश ऐसी उथल-पुथल का प्रबंधन कैसे कर लेते हैं जबकि अन्य देश नहीं कर पाते? हम दो दशक से भी पहले जाकर पूर्व सोवियत संघ यानी जॉर्जिया, किर्गीजस्तान, युगोस्लाविया और यहां तक कि यूक्रेन की 'रंग क्रांति' की बात करते हैं। उसे रंग क्रांति इसलिए कहा गया क्योंकि प्रदर्शनकारी हर देश के हो रहे प्रदर्शनों को रेखांकित करते हुए खास रंग की कमीज पहनते थे। इसके बाद अरब उभार और तहरीर चौक का आंदोलन सामने आया। हर एक का अंत बहुत त्रासद रहा। या तो एक नई तानाशाही का आगमन हुआ या फिर युगोस्लाविया की तरह देश का विभाजन हो गया। गूगल पर नई दिल्ली, 2011, रामलीला मैदान, तहरीर चौक सर्च कीजिए। गूगल आपको बताएगा कि ऐसे भी चतुर लोग हैं जिन्होंने अन्ना आंदोलन को 'भारत का तहरीर चौक' करार दिया था। ऐसा लग रहा था कि हर कोई बदलाव चाहता था, एक नई व्यवस्था और हालांकि कहा नहीं गया लेकिन शायद लोग एक नया संविधान भी चाहते थे। यह कहा जा रहा था कि हमें व्यवस्था को बदलना चाहिए। आखिरकार चुनाव के जरिये सरकार बदली गई। भारत तहरीर चौक जैसी किसी घटना से बच गया। उस आंदोलन का ईंधन था राजनीति यथास्थिति को लेकर लोगों की नाराजगी। अन्ना हजारे के मंच से अभिनेता ओम पुरी ने कहा था कि लोकतंत्र के कारण 'अनपढ़ और गंवार' लोग सत्ता में आ गए हैं। इस राजनीति को बदलकर चतुर, शिक्षित लोगों, नोबेल विजेताओं और मैगसेसे विजेताओं को सत्ता में आना चाहिए, ऐसी भावना थी। लग रहा था मानो बस बहुत हो चुका।

मध्य वर्ग और उच्च वर्ग दोनों साथ थे और उनके साथ तमाम उदारवादी, वामपंथी, दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी, अराजक वर्ग और मीडिया का अधिकांश वर्ग उनके साथ था। खासतौर पर समाचार प्रसारित करने वाले टेलीविजन चैनल। ऐसे टीआरपी प्रदान करने वाले अवसर का लाभ तो उन्हें उठाना ही था। मीडिया जगत के कुछ सितारों ने अन्ना के मंच से भी अपनी बात कही। कुछ ने सेना के नेतृत्व से साथ देने का आह्वान किया। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने के लिए जयप्रकाश नारायण के अपेक्षाकृत निरापद आह्वान का सहारा लिया था जिसमें उन्होंने सैन्य और पुलिस बलों से कहा था कि वे 'विधि विरुद्ध' आदेशों को न मानें। मनमोहन सिंह इंदिरा नहीं थे। हम उस तबाही से बच सके, इसके तीन कारण थे। उस समय चाहे जैसी भी हवा रही हो लेकिन हर व्यक्ति बदलाव नहीं चाहता था। टीवी चैनल, स्वयंसेवी संगठन, फिल्मी कलाकार और सितारा एंकर आदि पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते। भारत की व्यवस्था उन करीब डेढ़ अरब लोगों पर निर्भर है जो उस पर यकीन रखते हैं। यही कारण है कि सैन्य या असैन्य प्रतिष्ठान के किसी व्यक्ति ने आंदोलन में शिरकत नहीं की।

दूसरी वजह यह रही कि राजनीतिक वर्ग ने संघर्ष किया। अगर इसे समझना हो तो 25 अगस्त 2011 को जन लोकपाल विधेयक पर लोक सभा के सत्र की वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए। जैसा कि मैंने उस वक्त दर्ज किया था, स्वर्गीय शरद यादव ने कहा था 'इससे पहले कि आप इस व्यवस्था को खारिज करें, याद रखिए कि गांधी और आम्बेडकर की समझदारी नहीं होती तो मेरे जैसे लोगों को तो दिल्ली में अपने पालतू पशु चराने तक का मौका भी नहीं मिलता।' उन्होंने कहा कि यह सदन इकलौती ऐसी जगह है जहां आप पूरे देश के चेहरे देख सकते हैं। जहां दलितों को समान अवसर है और घुरऊ राम, गरीब राम और पकौड़ी लाल जैसे नामों वाले लोग सांसद हैं। एक पकौड़ी लाल या गरीब राम देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने के मामले में किसी भी नोबेल विजेता से कहीं अधिक सक्षम हैं। भारत में तहरीर चौक जैसी स्थिति न बनने की यह तीसरी वजह थी।

भारत इससे मजबूत होकर उभरा क्योंकि उसके सबसे गरीब लोगों में भी लोकतांत्रिक धैर्य था। ठीक वैसे ही जैसे नेपाल और श्रीलंका के लोगों में। अमेरिका में कैपिटल हिल पर कब्जे की कोशिश के साथ 2020 के चुनाव परिणामों को बदलने की डॉनल्ड ट्रंप की कोशिशों को जिस प्रकार खारिज किया गया वह भी इसका उदाहरण है। बांग्लादेश के लोगों ने इसके विपरीत काम किया। वहां अनिर्वाचित केयरटेकर बिना राजनेताओं के एक नया संविधान बनाना चाहते हैं और उसके बाद चुनाव करवाना चाहते हैं। यह ठीक पाकिस्तान की शैली है। लगता तो यही है परिणाम बहुत अच्छे नहीं होंगे। अगर आप शोर शराबा और अराजकता नहीं झेल सकते तो आप लोकतंत्र के लायक नहीं हैं।

तकनीक की बदौलत कैसे कही जाएगी बेहतरीन कहानी?

मीडिया मंत्र
वनिता कोहली-खांडेकर

आईमैक्स ने 1960 के दशक में ऐसे अत्याधुनिक स्क्रीन डिजाइन किए, जो दर्शकों को सम्मोहित ही कर लेते थे। इनका ज्यादातर इस्तेमाल संग्रहालयों में या इतिहास से जुड़े वृत्तचित्र (डॉक्यूमेंट्री) बनाने में किया जाता था। आईमैक्स का अधिग्रहण 1994 में एक निवेश बैंकिंग फर्म ने कर लिया, जिसे एक साझेदार के साथ चला रहे वकील और उद्यमी रिचर्ड गेलफॉण्ड कंपनी के निदेशक मंडल में आ गए। गेलफॉण्ड अब कंपनी के मुख्य कार्य अधिकारी (सीईओ) हैं। उस समय मुख्यधारा के स्टूडियो और थिएटर कंपनियों को इस तकनीक के इस्तेमाल के लिए राजी करना लगभग असंभव था। इस तकनीक पर फिल्में देखना एकदम अद्भुत लगता था मगर यह बेहद खर्चीला और बेतरतीब था।

उसी बीच वर्ष 2001 में आईमैक्स ने एक एल्गोरिदम तैयार किया, जिसकी मदद से वह आम फिल्मों को आईमैक्सस तकनीक में फॉर्मैट कर पाई और खर्च काफी कम हो गया। उसी वक्त थिएटर डिजिटल होने लगे थे और फिल्मकार भी आईमैक्स उपकरणों का इस्तेमाल कर फिल्में बनाने लगे थे।

2006 तक 'हैरी पॉटर ऐंड द गॉबलेट ऑफ फायर', 'हैपी फीट' और 'ट्रांसफॉर्मर्स' जैसी फिल्मों के कारण आईमैक्स फॉर्मैट अजनबी नहीं रह गया और 2009 में जेम्स कैमरॉन की सुपरहिट फिल्म 'अवतार' इसे पूरी तरह मुख्यधारा में ले आई। इस फिल्म ने दुनिया भर में करीब 3 अरब डॉलर कमाए और इसमें से 25 करोड़ डॉलर (लगभग 9 प्रतिशत) 163 आईमैक्स स्क्रीन से ही आए। 2023 तक यह तकनीक दुनिया भर में 1,705 स्क्रीन पर आ गई मगर यह संख्या कुल स्क्रीन के 1 प्रतिशत से भी कम थी। फिर भी फिल्मों से दुनिया भर में होने वाली कमाई में 3.5 प्रतिशत (1 अरब डॉलर से ज्यादा) आईमैक्स से ही आई। इसकी वजह दर्शक हैं, जो 'आईमैक्स' फिल्म देखने के लिए आम टिकट के मुकाबले तीन से पांच गुना कीमत खर्च करने को तैयार हैं।

2014 में आई जॉनथन और क्रिस्टॉफर नॉलन की फिल्म 'इंटरस्टेलर' में ब्लैकहोल के रास्ते दूसरे युग और दूसरी दुनिया में पहुंचने की कहानी थी। ब्लैकहोल और दूसरी दुनिया का न तो कोई सबूत है और न ही कोई तस्वीर। लेकिन खगोल-भौतिकीविद तथा नोबेल से सम्मानित किप थॉर्न ने अवार्ड जीतने वाली विजुअल इफेक्ट फर्म डीएनईजी के साथ मिलकर इसे साकार कर दिया। इंटरस्टेलर ने पूरी दुनिया में 70.5 करोड़ डॉलर से अधिक कमाए और विज्ञान पत्रिकाओं ने इसकी जमकर तारीफ की। मुंबई की कंपनी प्राइम फोकस की सहायक फर्म डीएनईजी ने इस फिल्म के लिए ऑस्कर भी जीता। डीएनईजी लंदन से काम करती है और इंटरस्टेलर के अलावा वह ड्यून (पार्ट वन), टेनेट तथा इंसेप्शन समेत छह अन्य फिल्मों के लिए भी ऑस्कर जीत चुकी है। प्राइम फोकस के संस्थापक और डीएनईजी के सीईओ नमित मल्होत्रा का कहना है कि फिल्मकार सपना देख सकते हैं तो उनकी फर्म उसे साकार कर सकती है।

कहानी कहने में हुई तकनीकी प्रगति में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) को भी जोड़ दीजिए। एआई की मदद से कहानी कहने की कोशिश में दुनिया और भारत के स्टार्टअप जुटे पड़े हैं। बेंगलूरु की न्यूरलगैराज जैसी कंपनियां विजुअलडब की सुविधा देती हैं। जेनरेटिव एआई वाली यह तकनीक किरदार के हावभाव और हरकतों के साथ डबिंग का ऐसा तालमेल बिठा देती है कि वीडियो को तेलुगु से कोरियाई या अंग्रेजी या हिंदी में डब किए जाने पर कुछ भी अटपटा नहीं लगता। ब्रिटानिया और अल्ट्राटेक जैसे ब्रांडों ने विविधता से भरे देसी उपभोक्ता बाजार में विज्ञापन फिल्में प्रदर्शित करने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया है। न्यूरलगैराज ने इसी साल डिजिटल सिनेमा वितरण फर्म यूएफओ मूवीज के साथ भी करार किया है ताकि स्टूडियो उसकी तकनीक का इस्तेमाल करें। कई भाषाओं में डब की गई फिल्में देश भर या दुनिया भर में दिखाने वाली स्ट्रीमिंग सेवाएं या थिएटर खर्च में एक तिहाई या ज्यादा कमी लाने वाली तकनीक का स्वागत क्यों नहीं करेंगे।

चेन्नई की कंपनी एशियाविल इंटरैक्टिव के ऐप एवी ने गेमिंग और फिक्शन को जोड़ने वाली तकनीक का पेटेंट कराया है। इसके 45-45 मिनट के दो शो में से एक 'हू किल्ड कविता' है। यह एक वीडियो है, जिसमें आपको सुराग ढूंढने होते हैं, संदिग्धों का पता लगाना होता है, लिखावट जांचनी होती है और ऐसे कई काम करने होते हैं। जी एंटरटेनमेंट ने जेनरेटिव एआईटूल स्क्रिप्टजीपीटी तैयार किया है, जो आपको किरदारों, कहानियों, पटकथाओं और उनमें आने वाले मोड़ को पहचानने तथा समझने में मदद करता है। इससे बड़ी तादाद में दर्शक आ सकते हैं और रेटिंग बढ़ सकती है।

स्क्रीनिंग और फिल्म निर्माण से लेकर लेखन और पटकथा तक तकनीक से आ रही रचनात्मकता कारोबार में तगड़ी उथलपुथल ला रही है। दुनिया भर में 2016 में शुरू हुई स्ट्रीमिंग भारी तादाद में दर्शकों को अपने साथ ले जा रही है। 2017 में दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर 42 अरब डॉलर की कमाई हुई थी, जो 2023 में घटकर 34 अरब डॉलर रह गई। लोगों को थिएटर में लाना है तो ऑपनहाइमर, बार्बी या पठान जैसा कुछ बिल्कुल अलग करना होगा। इसका मतलब है कि आपको या तो भव्यता और विजुअल इफेक्ट डालने होंगे या ऐसा सितारा लाना होगा, जिसे दर्शक छोटे पर्दे के बजाय बड़े पर्दे पर ही देखना चाहते हैं। साथ ही आपको स्क्रीन भी ऐसा चाहिए, जिस पर फिल्म देखने के लिए दर्शक घर से निकलने को मजबूर हों। लेकिन सवाल बरकरार है कि कब तकनीक कहानी का सहारा बनना बंद कर देती है और खुद कहानी बन जाती है? किसी कहानी को कितने और किस तरह के विजुअल इफेक्ट, टूल या गिज्मो की जरूरत है यह दर्शकों और फिल्मकारों को ही तय करना है। मल्होत्रा कहते हैं, 'तकनीक, टूल, सुपरस्टार का कोई मतलब नहीं है। लोगों को केवल कहानी से मतलब होता है। निर्देशक दूसरे काल और दूसरी दुनिया में जाने की कहानी दिखाना चाहता है तो वह जरूरी टूल्स के बगैर ऐसा नहीं कर सकता। ये सब कहानी की जरूरत पूरी करने के लिए ही हैं।'

यह सोचने वाली बात है। ऑपनहाइमर या ड्यून भव्य फिल्में नहीं हैं। वे असाधारण, वास्तविक या काल्पनिक घटनाओं तथा माहौल की कहानी हैं। मिशन इंपॉसिबल, फ्यूरिओसा और ब्रह्मास्त्र में कहानी के साथ भव्यता भी है। दोनों तरह की फिल्में कामयाब रहीं मगर हाल में मारवल की कई फिल्में या स्पेशल इफेक्ट से भरी फिल्में कहानी में दम नहीं होने की वजह से चित हो गईं।

तकनीक में जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल हो या न हो, यह बात दोनों पर लागू होती है। जेनरेटिव एआई जैसी समझ भरी तकनीक के साथ एक पेच और है। इसे सिखाना पड़ता है, जो पुरानी फिल्मों या कार्यक्रमों के जरिये ही मुमकिन है। अब लेखक, फिल्मकार और अभिनेता कानून का सहारा ले रहे हैं ताकि एआई को सिखाने के लिए उनकी फिल्मों का इस्तेमाल नहीं किया जा सके। ऐसे में जेनरेटिव एआई को कुछ भी तैयार या जेनरेट करने के लिए पर्याप्त सामग्री या डेटा ही नहीं मिलेगा या उसे सीखने के लिए घटिया वीडियो अथवा कहानियां ही मिलेंगी। इससे वह घटिया सामग्री ही तैयार कर पाएगी। फिलहाल एआई देखने का अनुभव बेहतर बनाने, खर्च घटाने, क्षमता बढ़ाने और कभी-कभार एआई से किरदार तैयार करने में ही इस्तेमाल की जा रही है।

आपका पक्ष

साइबर अपराध पर लगाम के हों पुख्ता इंतजाम

देश में ऑनलाइन शॉपिंग और भुगतान का दायरा जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उसी रफ्तार से साइबर ठगी भी पांव पसार रही है। ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले अपराधी हर रोज कोई नया हथकंडा अपना रहे हैं। लोगों की कड़ी मेहनत की कमाई चुटकियों में साइबर अपराधियों की जेब में जा रही है। यही वजह है कि ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग और अन्य आर्थिक धोखाधड़ी संबंधी खबरें आए दिन सामने आ रही हैं। ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन भुगतान करने वालों की हालत यह हो गई है कि मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर मिलने वाला हर अनजाना एसएमएस और ई-मेल संदिग्ध लगने लगा है। साइबर अपराधों के हथकंडों की कम जानकारी रखने वाले लोग तो आसानी से इनके झांसे में आ ही रहे हैं, साथ ही इनके दांव-पेचों से अवगत लोग भी इनका शिकार हो रहे हैं। और तो और एटीएम, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए भी लोगों के साथ ठगी हो रही है। फिशिंग, जूस जैकिंग और हनी-ट्रैप जैसी चीजें तो और भी खतरनाक हैं। ऐसे भी कई मामले सामने आ चुके हैं जिनमें ऑनलाइन शॉपिंग या नया-पुराना सामान बेचने के नाम पर ग्राहकों से पैसा वसूल लिया जाता है और बदले में उन्हें या तो कुछ भी नहीं मिलता या फिर घटिया सामान भेज दिया जाता है।

मनीष त्रिपाठी, भोपाल

ऑनलाइन शॉपिंग या नया-पुराना सामान बेचने के नाम पर ग्राहकों से पैसा वसूल लिया जाता है और बदले में घटिया सामान भेजा जाता है

मिलावटखोरों का जाल, आस्था से खिलवाड़

मिलावटखोरों ने तिरुपति के विश्व प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर को भी नहीं छोड़ा। तिरुपति स्थित मंदिर का प्रबंधन करने वाले तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) ने लैब रिपोर्ट का हवाला देते हुए साफ कहा कि मंदिर को आपूर्ति किए जाने वाले घी में पशु की चर्बी समेत अन्य मिलावटी अंश मिले हैं। ऐसी खबरें आस्था पर गहरी चोट हैं। सवाल यह है कि इस विश्व प्रसिद्ध पवित्र स्थल पर खाद्य सामग्री कहां से आ रही है, उसे बनाने में किन मानकों का पालन किया जा रहा है और आपूर्ति के स्तर पर क्या सावधानी बरती जा रही है? यह देखना तो मंदिर प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है। उसके स्तर पर यह लापरवाही क्यों हुई? दूसरा सवाल सरकार से भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर एक फैक्टरी में मिलावट का धंधा चलता रहा और आपूर्तिकर्ता बेखौफ होकर लोगों की आस्था से खिलवाड़ करता रहा, लेकिन स्थानीय प्रशासन कहां सोया हुआ था? विश्व प्रसिद्ध मंदिर में मिलावट के मामले के उजागर होने से स्पष्ट संकेत मिलता है कि खाद्य सामग्री में मिलावट का धंधा किस स्तर तक अपनी पैठ बना चुका है और इसे रोकने के लिए बनाए गए कानून कितने कमजोर साबित हो रहे हैं। देश ही नहीं, दुनिया भर से श्रद्धालु तिरुपति दर्शन के लिए आते हैं और यहां से प्रसाद लेकर जाते हैं। लोग बड़ी श्रद्धा से इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि मामले की तह तक जाकर दोषियों का पता लगाया जाना चाहिए। घी आपूर्तिकर्ता, मंदिर प्रबंधन के जिम्मेदार पदाधिकारी और प्रशासन के संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब होना चाहिए। देश में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कोई मिलावट के बारे में सोच भी न सके।

राजेश कुमार, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

बेंगलूरु के नैशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के 32वें दीक्षांत समारोह के दौरान रविवार को छात्रा को डिग्री प्रदान करते भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी। इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ भी मौजूद रहे।